

श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह

उपराज्यपाल ने एसएमवीडीयू के स्नातक छात्रों को आशीर्वाद देने के लिए भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आभार व्यक्त किया

उपराज्यपाल ने युवाओं से देश के विकास को आगे बढ़ाने और इसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का आह्वान किया

हमारे राष्ट्र की ताकत मूल्यों, नवाचार और ज्ञान से निर्धारित होगी और मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस अमृत काल में स्नातक होने वाले युवा पुरुष और महिलाएं हमारे राष्ट्र की नियति को आकार देंगे-एलजी

आज वास्तविक दुनिया में कदम रखने वालों के पास राष्ट्र निर्माण का एक अनूठा अवसर है-एलजी सिन्हा

कौशल और ज्ञान को लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहिए-एलजी सिन्हा

कटरा



उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।

उपराज्यपाल ने विष्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में एसएमवीडीयू के स्नातक छात्रों को आशीर्वाद देने के लिए भारत के

माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, आज का क्षण छात्रों की यादों में जीवन भर अंकित रहेगा।

सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने युवाओं से देश के विकास को आगे बढ़ाने

और इसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का आह्वान किया।

उपराज्यपाल ने कहा हमारे राष्ट्र की ताकत मूल्यों, नवाचार और ज्ञान से निर्धारित होगी और मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस अमृत काल में स्नातक होने वाले युवा पुरुष और महिलाएं

हमारे राष्ट्र की नियति को आकार देंगे। आज वास्तविक दुनिया में कदम रखने वालों के पास राष्ट्र निर्माण का एक अनूठा अवसर है।

उन्होंने कहा कि मानविकी, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति ने अवसरों के नए क्षेत्र खोले हैं और स्नातक छात्रों का ज्ञान और

सीख उन्हें सफलता हासिल करने में मदद करेगी। आज हमारे युवा विशेष ज्ञान और कौशल से लैस हैं जिनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों को बदलने के लिए उचित रूप से किया जा सकता है। यह मिशन समर्पण और दृढ़ संकल्प की मांग करता है। सबसे बढ़कर, हमारे युवाओं को प्राचीन संस्कृति में निहित होने की जरूरत है और उन्हें अपनी क्षमताओं और हमारी संस्कृति के ज्ञान पर विश्वास होना चाहिए।

उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि कौशल और ज्ञान को लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहिए।

उपराज्यपाल ने आगे कहा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भविष्य के अवसरों का लाभ उठाने के लिए, हमें अपनी शिक्षण-परामर्श प्रणाली पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है क्योंकि इसका सीधा असर विकसित भारत की यात्रा पर पड़ेगा।

उपराज्यपाल ने शिक्षण समुदाय से हमारे छात्रों की

शेष पृष्ठ 15 पर

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु प्रतिबद्ध है-एलजी

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कई सहायक उपकरणों को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाया है-एलजी

जम्मू

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने गुलशन ग्राउंड में 11 दिवसीय दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया, जो दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार की एक अनूठी पहल है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम



के सहयोग से आयोजित किए जा रहे दिव्य कला मेले में दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों और जम्मू-कश्मीर यूटी और विभिन्न अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकारों की असाधारण प्रतिभा, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना का प्रदर्शन किया गया। अपने संबोधन में

उपराज्यपाल ने भारत सरकार और इस नेक प्रयास से जुड़े सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की माननीय प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

शेष पृष्ठ 15 पर

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्कॉस्ट-जम्मू में पंचायत सचिवों को नियुक्ति आदेश वितरित किए सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता, प्रतिबद्धता पर जोर दिया

जम्मू

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी, पारदर्शिता और समर्पण के महत्व पर प्रकाश डाला।

यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग, जम्मू-कश्मीर में नव नियुक्त पंचायत सचिवों को नियुक्ति आदेश वितरित करने के लिए आयोजित किया गया था।

नियुक्तियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें सरकार और लोगों के बीच की दूरी को पाटने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाई। उन्होंने कहा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी थी, हालांकि इसमें चुनौतियाँ थीं। कठिनाइयों के बावजूद, हमने सुनिश्चित किया कि प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से पूरी हो।



आज आपको नियुक्ति आदेश किसी के उपकार के रूप में नहीं, बल्कि आपकी कड़ी मेहनत और योग्यता के परिणाम के रूप में प्राप्त हुए हैं।

जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास को याद करते हुए, उमर अब्दुल्ला ने जमीनी

शेष पृष्ठ 15 पर

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में पहली बार राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन, मेडिकॉन-2025 को संबोधित किया

मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया, समान स्वास्थ्य देखभाल का आह्वान किया

जम्मू

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रमुख अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आपातकालीन मामलों से निपटने और क्षमता में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर दिया कि डॉक्टर शहरी केंद्रों से परे भी सेवा करें। हमें नए जीएमसी में आपातकालीन प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने और सुधारने की जरूरत है ताकि जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर पर दबाव स्वचालित रूप से कम हो जाए। इसी तरह, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे डॉक्टर सिर्फ शहरों में प्रैक्टिस न करें। मैं जानता हूँ कि यह कहना कोई लोकप्रिय बात नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र भी उचित स्वास्थ्य देखभाल पहुंच के हकदार हैं।

मुख्यमंत्री ने यह बात सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू में पहली बार राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-कार्यशाला जेके मेडिकॉन-2025 को संबोधित करते हुए कही।

यह कार्यक्रम जेएंडके मेडिकल काउंसिल द्वारा छत्र अनुसंधान विकास परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया।

सम्मेलन में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तु, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक



अब्दुल्ला, सचिव एच एंड एमई डॉ. सैयद आबिद रशीद, जम्मू पश्चिम विधायक अरविंद गुप्ता, जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल और डीन डॉ. आशुतोष गुप्ता, जेके मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. मुहम्मद सलीम खान, वरिष्ठ प्रोफेसर, डॉक्टर, संकाय और छात्र उपस्थित थे।

उमर अब्दुल्ला ने पूरे जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा पहुंच में सुधार के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा हमारी चुनौती स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ बनाना है। प्रोफेसर गुप्ता ने जीएमसी जम्मू की आपातकालीन सेवाओं पर अत्यधिक दबाव की ओर इशारा किया, जो इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि परिधीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा आवश्यक मानक की नहीं है। यह लोगों को शहरों में घुसने के लिए मजबूर करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसका समाधान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।

इस दबाव को कम करने का तरीका सिर्फ जम्मू में हमारे बुनियादी ढांचे का विस्तार करना नहीं है, बल्कि परिधीय क्षेत्रों में

सुविधाओं को मजबूत करना है। एक समय था जब हमारे पास केवल जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर थे। अब, हमारे पास जिला स्तर पर जीएमसी हैं।

मेडिकॉन-2025 के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने प्रमुख चिकित्सा मुद्दों पर बहस और चर्चा को बढ़ावा देने में इसके महत्व को स्वीकार किया।

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि प्रतिभागी मेडिकॉन के माध्यम से 11 क्रेडिट अर्जित करेंगे, जो अधिक जुड़ाव और उत्साह को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि चिकित्सा विज्ञान में भविष्य की प्रगति हमारी चर्चाओं का हिस्सा होगी, तकनीक कितनी फायदेमंद है, मशीनों द्वारा मानव संपर्क को कितना प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ कार्य एआई द्वारा बेहतर ढंग से किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो केवल मनुष्य ही कर सकते हैं।

आधुनिक चिकित्सा प्रवृत्तियों के नैतिक आयामों को छूते हुए, उमर अब्दुल्ला ने चिकित्सा और लाभ-संचालित स्वास्थ्य सेवा के अंतर्संबंध के बारे में चिंता जताई।

उन्होंने कॉर्पोरेट अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों पर दबाव का भी उल्लेख किया, जहां उनका प्रदर्शन उनके द्वारा इलाज किए जाने वाले मरीजों की संख्या से नहीं बल्कि उनके द्वारा उत्पन्न राजस्व से मापा जाता है।

चिकित्सा में रोबोटिक सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने इन प्रगति से जुड़ी संभावनाओं और चिंताओं दोनों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा एक प्रवृत्ति जो जोर पकड़ती दिख रही है वह है रोबोटिक सर्जरी का उपयोग। प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू ने उल्लेख किया कि एआई एक दिन चिकित्सा प्रक्रियाओं पर कब्जा कर सकता है। ईमानदारी से कहूं तो, मैं अपना जीवन पूरी तरह से एक मशीन को सौंपने से ज्यादा डरावनी संभावना की कल्पना नहीं कर सकता। दिन के अंत में, मानव संपर्क का अत्यधिक मूल्य है, और यहीं पर डॉक्टर जो सचमुच भगवान का काम करते हैं एक अपूरणीय भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने डॉक्टरों के समर्पण और

आजीवन सीखने की सराहना की। उन्होंने कहा, आप लोगों को मौत के मुंह से वापस खींच लेते हैं। आप वहां आशा देते हैं जहां सारी आशा खो जाती है। आप मरीजों और उनके परिवारों के सबसे कमजोर क्षणों में उनके साथ खड़े रहते हैं चाहे वह ठीक होने में हो या नुकसान के समय में।

डॉक्टर के रूप में, आप कभी भी सीखना बंद नहीं करते हैं। आप हमेशा नई तकनीकों, दवाओं और उपचार विधियों को अपना रहे हैं। लेकिन जब कोई डॉक्टर निदान या पूर्वानुमान देता है तो कोई भी मशीन मानवीय स्पर्श की जगह नहीं ले सकती। मरीज और उनके परिवार डॉक्टर के कहे हर शब्द को मानते हैं।

मुख्यमंत्री ने जीएमसी जम्मू के लिए विकास योजनाओं को भी स्वीकार किया और योगदान देने का इरादा व्यक्त किया।

उन्होंने कहा प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू ने जीएमसी जम्मू के भविष्य के विकास के लिए कई विचार प्रस्तुत किए। मैं और मेरे सहकर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम उन प्रस्तावों में से एक को लागू किया जाए ताकि मैं भी यहां आधारशिला रख सकूँ और भविष्य की प्रस्तुतियों में खुद को अलग-थलग महसूस न करूँ।

उन्होंने मेडिकॉन-2025 के महत्व को भी रेखांकित किया जहां किसी राज्य या क्षेत्रीय चिकित्सा परिषद ने इस तरह का आयोजन किया है।

उन्होंने कहा, यह कार्यक्रम चिकित्सा में उभरते रुझानों पर चर्चा करते हुए विचारों, सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुसंधान प्रगति को साझा करने के लिए सर्वोत्तम दिमागों को एक साथ लाता है।

इससे पहले, जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल ने कॉलेज के विकास और भविष्य की योजनाओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

महामंडलेश्वर साध्वी संजनानंद गिरि जी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की



जम्मू

महामंडलेश्वर साध्वी संजनानंद गिरि जी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और आगामी चतुष्पथ यात्रा पर चर्चा की, जो समाज के उत्थान, आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने, पर्यावरण जागरूकता और लोक कल्याण के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी आध्यात्मिक यात्रा है। बैठक के दौरान, महामंडलेश्वर संजनानंद गिरि जी ने यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला, जो शांति, सद्भाव और टिकाऊ जीवन का

संदेश फैलाते हुए जम्मू और कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश में यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। चतुष्पथ यात्रा की कल्पना सामूहिक चेतना को प्रेरित करने, सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने और लोगों के बीच आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हुए स्वच्छ, हरित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक आंदोलन के रूप में की गई है।

सूचना निदेशक ने विभाग के प्रदर्शन, कार्यप्रणाली की समीक्षा की मीडिया समन्वय को मजबूत करने, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक जुड़ाव को बेहतर बनाने पर जोर दिया

जम्मू

निदेशक सूचना जम्मू-कश्मीर नितीश राजोरा ने सार्वजनिक पहुंच, कुशल संचार रणनीतियों, सरकारी पहलों के समय पर प्रसार के साथ-साथ मीडिया समन्वय को मजबूत करने और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सार्वजनिक जुड़ाव में सुधार पर जोर दिया। निदेशक ने यह बात मीडिया कॉम्प्लेक्स में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रदर्शन और कामकाज की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। संयुक्त निदेशक सूचना (मुख्यालय), विवेक पुरी, संयुक्त निदेशक सूचना जम्मू अतुल गुप्ता, संयुक्त निदेशक सूचना कश्मीर शाहनवाज भुखारी, उपनिदेशक सूचना (पीआर) दीपक दुबे, उप निदेशक सूचना (केंद्रीय) सुनील कुमार, उप निदेशक पीआर कश्मीर अहसान उल हक चिश्ती, उप निदेशक पीआर जम्मू अंकुश हंस, सांस्कृतिक अधिकारी, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, सूचना अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या



वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान निदेशक ने जनता की भलाई के लिए सक्रिय संचार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं और नीतिगत निर्णयों को उजागर करने के लिए नवीन दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। निदेशक ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने, वास्तविक समय के अपडेट और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का लाभ

उठाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से फर्जी खबरों को खारिज करने के लिए समय पर रणनीति अपनाने का आह्वान किया। विभाग में जनशक्ति की स्थिति और अन्य मुद्दों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों से विभाग के कर्मचारियों को जनसंपर्क के नवीनतम रुझानों से अवगत कराने के लिए नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने का भी आह्वान किया।

उपमुख्यमंत्री ने शोपियां में विकास गतिविधियों की समीक्षा की सभी परियोजनाओं पर काम की गति में तेजी लाने का निर्देश दिया

शोपियां

शोपियां जिले के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चैधरी ने कनेक्टिविटी और बागवानी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया।

उपमुख्यमंत्री ने ये निर्देश मिनी सचिवालय शोपियां में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं और योजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक के दौरान दिये।

बैठक में विधायक वाची शौकत गनिया और शोपियां के विधायक शब्बीर कुल्ले, विभिन्न विभागों के एचओडी और क्षेत्रीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

शुरुआत में, शोपियां के उपायुक्त शिशिर गुप्ता ने अध्यक्ष को जिले में विकासात्मक परिदृश्य और चल रहे कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

लोक निर्माण विभाग, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क और भवन विभाग, जेजेएम और अन्य की समीक्षा करते हुए, उपमुख्यमंत्री ने कुछ कार्यों में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने और परियोजना की समय सीमा का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और उन्हें शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।

उपमुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समय पर और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के महत्व को रेखांकित किया और अधिकारियों को तकनीकी विशिष्टताओं और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले के लोगों को दीर्घकालिक लाभ पहुंचाने के लिए टिकाऊ निर्माण प्रथाओं की आवश्यकता पर भी जोर



दिया।

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से विकासात्मक पहलों में तेजी लाने और सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने सरकारी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जनता के लिए सुलभ होने के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा हम जिले भर में विकास में तेजी लाने और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं। योजनाएं बनाते समय निर्वाचित प्रतिनिधियों के सुझावों और फीडबैक को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए

ताकि वे स्थानीय जरूरतों और मांगों के अनुरूप बन सकें।

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चुनौतियों, यदि कोई हो, से निपटने में सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा कि हम विकास कार्यों के सुचारू कार्यान्वयन में मदद करेंगे। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चल रहे सभी कार्यों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन का आह्वान किया।

उपमुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, सरकार सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को चरणबद्ध तरीके

से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि लोगों ने इसे चुना है और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कुछ कार्यों में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए सावधानीपूर्वक योजना और कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिक समर्पण के साथ काम करने और सभी चल रहे कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये परियोजनाएं जिले के समग्र विकास और लोगों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। उपमुख्यमंत्री ने प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत

जानकारी ली और परियोजना कार्यान्वयन के सभी चरणों में उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के अलावा समय सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान, अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं पर प्रगति के बारे में अपडेट प्रदान किया और धन की कमी, भूमि अधिग्रहण के मुद्दों और तकनीकी कठिनाइयों सहित चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

विधायकों ने अपने संबंधित क्षेत्रों के सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिसमें पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों का विस्तार और जैनापोरा में अन्य विकासात्मक गतिविधियां और जिला अस्पताल शोपियां में शोपियां कार्डियोलॉजिस्ट, टाउन शोपियां का सौंदर्यीकरण, बाई-पास के तहत भूमि का मुआवजा और अन्य मुद्दे शामिल हैं।

बाद में उपमुख्यमंत्री ने 39.41 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बन रहे ट्रेज ब्रिज के काम की गति का निरीक्षण किया।

मौके पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए उन्होंने दो जिलों को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण पुल को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि काम की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

उपमुख्यमंत्री ने जैनापोरा में 18.84 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बन रहे डिग्री कॉलेज के चल रहे काम का भी निरीक्षण किया।

उनके साथ विधायक वाची, शोपियां के उपायुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति के केंद्र में हैं – सतीश शर्मा

जैव विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी में उभरते रुझानों पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया साथ ही पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी

जम्मू

एफसीएस और सीए, परिवहन, युवा सेवा और खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सतीश शर्मा ने एसएमवीडीयू कटरा में बायोसाइंसेज और रासायनिक प्रौद्योगिकी, 2025 में उभरते रुझानों पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

इस अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो. प्रगति कुमार, एसएमवीडी कॉलेज ऑफ मेडिकल एक्सिलेंस



के कार्यकारी निदेशक डॉ. यशपाल शर्मा, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के प्रमुख प्रो. रत्ना चंद्रा और सम्मेलन के संयोजक डॉ. इंदु भूषण शर्मा भी उपस्थित थे। सम्मेलन की

शुरुआत में मंत्री ने पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और दो मिनट का मौन भी रखा गया।

सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री ने

वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के समर्पण की सराहना की और कहा कि शैक्षणिक उत्कृष्टता वास्तव में सराहनीय है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सम्मेलन हमारी लगातार विकसित हो रही दुनिया में अभूतपूर्व प्रगति और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।

सतीश शर्मा ने जैव विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ बेहतरीन दिमागों को एक साथ लाने के लिए एसएमवीडीयू और आयोजन समिति को बधाई दी।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति के केंद्र में हैं, और आज की तेजी से विकसित हो रही दुनिया में, जैव विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ऊर्जा या पर्यावरणीय स्थिरता हो।

उन्होंने कहा, जैव विज्ञान के क्षेत्र में, हम जीनोम संपादन और पुनर्योजी चिकित्सा से लेकर सिंथेटिक जीव विज्ञान और व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल तक अभूतपूर्व नवाचार देख रहे हैं। इन प्रगतियों में बीमारी की रोकथाम, दवा की खोज और कृषि सुधार, सभी के लिए खाद्य

सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने की अपार संभावनाएं हैं।

मंत्री ने आह्वान किया कि जम्मू और कश्मीर समृद्ध जैव विविधता, उपजाऊ भूमि और विशाल प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सही दृष्टिकोण और नवाचार के साथ, हम सतत विकास और आर्थिक विकास के लिए नए अवसरों को अनलॉक कर सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब के गतिशील नेतृत्व में वर्तमान सरकार अनुसंधान, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी-संचालित विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा, हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में केंद्र सरकार से भी अच्छा समर्थन और मार्गदर्शन मिल रहा है। सम्मेलन सत्रों के समानांतर, बायोटेक्नोलॉजी स्कूल में बायोसाइंसेज में कौशल पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों को विभिन्न बायोसाइंसेज अनुप्रयोगों में व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया गया।

दिन का समापन गहन चर्चाओं, नेटवर्किंग अवसरों और प्रतिभागियों के बीच आकर्षक बातचीत के साथ हुआ।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी, पुंछ के जन प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया

जम्मू

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने चल रहे बजट-पूर्व परामर्श के हिस्से के रूप में नागरिक सचिवालय में पुंछ और राजौरी जिलों के जन प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया।

चर्चा में उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी और मंत्री जावेद अहमद राणा ने भाग लिया, जिन्होंने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। राजौरी और पुंछ के दोनों जिलों से जिला विकास परिषदों के अध्यक्षों और विधान सभा के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से और वर्चुअल मोड के माध्यम से भाग लिया।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने दोहराया कि इन परामर्शों का उद्देश्य अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा जब हम नई परियोजनाएं शुरू करते हैं, तो यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि चल रही परियोजनाएं नई परियोजनाओं की तरह ही प्राथमिकता के साथ पूरी हों। हर परियोजना लोगों की है, और सभी चल रहे



कार्यों को समय पर पूरा करने की जरूरत है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों और प्राथमिकताओं पर विधिवत ध्यान दिया गया है और आगामी बजट में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

आप प्राथमिक हितधारक हैं, आप प्रतिदिन लोगों से मिलते हैं और उनकी सबसे गंभीर चिंताओं को समझते हैं। हमारा

उद्देश्य आपको योजना और विकास में शामिल करना है ताकि लोगों की आवाज को हमारे शासन में जगह मिल सके।

बैठक के दौरान, राजौरी और पुंछ के उपायुक्तों ने पूंजीगत व्यय कार्यों पर जिलेवार अपडेट प्रस्तुत किए जिन्हें जम्मू और कश्मीर विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्राथमिकता दी जाएगी।

इस अवसर पर, उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी, जो नौशेरा विधानसभा क्षेत्र

का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिसमें डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, पेयजल आपूर्ति चुनौतियां, मोबाइल नेटवर्क मुद्दे, पुल, सड़क उन्नयन और अखनूर से आगे राजौरी-पुंछ रोड को चार लेन का बनाने का मुद्दा शामिल है। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन विकास की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

इसी तरह, मेंढर विधानसभा क्षेत्र का

प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री जावेद अहमद राणा ने पेयजल आपूर्ति, नए जल स्रोतों की पहचान, बिजली, पर्यटन विकास, रोजगार और शिक्षा से संबंधित चिंताओं को उठाया।

संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के अन्य विधायकों ने भी अपनी मांगें और मुद्दे प्रस्तुत किए, जिनमें पर्यटन, कृषि, बागवानी और शहरी विकास सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया।



संभागीय आयुक्त ने सुरिसर-मानसर वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जोनल मास्टर प्लान पर चर्चा की



जम्मू

संभागीय आयुक्त जम्मू रमेश कुमार, जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए संभागीय स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं, ने सुरिसर मानसर वन्यजीव अभयारण्य हेतु जोनल मास्टर प्लान तैयार करने पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में सांबा, उधमपुर के उपायुक्तों, क्षेत्रीय वन्यजीव वार्डन, क्षेत्रीय निदेशक पारिस्थितिकी और रिमोट सेंसिंग, डीएफओ के अलावा कृषि और संबद्ध विभागों के

अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें वन्यजीव अभयारण्य की परिधि से 10 किलोमीटर के भीतर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के संरक्षण के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई।

इस बात पर जोर दिया गया कि इको सेंसिटिव जोन के विकास का उद्देश्य वन्यजीव अभयारण्य की वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करना है।

बैठक में संबंधित विभागों द्वारा ईको सेंसिटिव जोन में प्रतिबंधित, विनियमित एवं प्रचारित की जाने वाली गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

संभागीय आयुक्त ने क्षेत्रीय वन्यजीव वार्डन और प्रभागीय वन अधिकारियों को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए गतिविधियों की सूची जिला प्रशासन को साझा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने मुख्य कृषि अधिकारियों को जैविक खेती और वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

बैठक में निर्णय एवं निर्देशों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा अगली बैठक में करने का निर्णय लिया गया।

बीएसएफ जम्मू फटियर के महानिरीक्षक ने उपराज्यपाल से भेंट की



जम्मू

बीएसएफ जम्मू फटियर के महानिरीक्षक शशांक आनंद ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भेंट की। उन्होंने उपराज्यपाल को उनकी जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी और सीमा सुरक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उपराज्यपाल ने समन्वित तरीके से किसी भी आकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच निरंतर सतर्कता और तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया।

डोडा पश्चिम के विधानसभा सदस्य ने उपराज्यपाल से भेंट की

जम्मू

डोडा पश्चिम से विधानसभा सदस्य शक्ति राज परिहार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भेंट की तथा उन्हें विभिन्न विकास मुद्दों से अवगत करवाया।

उपराज्यपाल ने जम्मू संभाग में सुरक्षा परिदृश्य पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

अधिकारियों को जम्मू क्षेत्र से आतंकवाद को समाप्त करने तथा आतंकवाद के बुनियादी ढांचे और स्थानीय समर्थन को पूरी तरह से नश्ट करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए

हमें आतंकवाद को वित्तीय सहायता प्रदान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है

आतंकवाद के हर अपराधी और समर्थक को इसकी कीमत चुकानी होगी-एलजी

उपराज्यपाल ने हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत उपाय करने का निर्देश दिया

जम्मू

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और जम्मू संभाग में सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की।

बैठक में डीजीपी जम्मू-कश्मीर नलिन प्रभात, एडीजीपी सशस्त्र आनंद जैन, एडीजीपी मुख्यालय एमके सिन्हा, एडीजीपी सीआईडी नीतीश कुमार, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मंदीप के. भंडारी, आईजीपी



जम्मू भीम सेन टूटी, आईजीपी अपराध डॉ. सुनील गुप्ता, आईजीपी सुरक्षा सुजीत कुमार, आईजीपी रेलवे विवेक गुप्ता, आईजीपी यातायात एम. सुलेमान चौधरी, रेंज डीआईजी, एसएसपी और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विभिन्न विंग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शुरुआत में, डीजीपी जम्मू-कश्मीर और आईजीपी जम्मू ने आम नागरिक के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भविष्य की कार्य योजना और प्रस्तावित उपायों पर अध्यक्ष को जानकारी दी।

आईजीपी रेलवे ने रेलवे की सुरक्षा वास्तुकला और स्टेशनों और पटरियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाए गए रोडमैप पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

उपराज्यपाल ने कहा कि हमारा ध्यान

जम्मू संभाग से आतंकवाद के पूर्ण सफाए पर होना चाहिए।

उन्होंने कहा हमें जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद का अवशेष भी नहीं छोड़ना चाहिए। आतंकवाद का सफाया करने और बुनियादी ढांचे और आतंकवाद के स्थानीय समर्थन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।

उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर पुलिस अधिकारियों को आतंकवाद को रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया, “यह सुनिश्चित करें कि समाज में भय पैदा करने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों या समूहों के कृत्यों को आतंकवादी कार्रवाई कहा जाए और उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जाए।”

उपराज्यपाल ने प्रौद्योगिकी संचालित पुलिसिंग, क्षेत्र वर्चस्व योजना, अंतर-एजेंसी समन्वय, नाकॉ-आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस बल की क्षमता निर्माण और साइबर गश्त और निगरानी क्षमताओं में सुधार के लिए अभिनव रणनीतियों के लिए रोडमैप पर भी चर्चा की। उन्होंने विश्वसनीय खुफिया जानकारी जुटाने, वास्तविक समय की परिचालन खुफिया जानकारी साझा करने और सटीक सुझाव के आधार पर आतंकवाद विरोधी अभियानों पर जोर दिया।

उपराज्यपाल ने कहा, “आतंकवाद के हर अपराधी और समर्थक को इसकी कीमत चुकानी होगी। हमें खुद को विश्वसनीय खुफिया जानकारी से लैस करने और आतंकवादियों को बेअसर करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है।

हमें पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए।” उपराज्यपाल ने हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत उपाय करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “हमें नदियों और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के साथ छिद्रपूर्ण सीमा के कारण विषम खतरों के खिलाफ सीमा सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए और सभी सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक बैक-अप सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।” उपराज्यपाल ने आतंकवादी प्रचारकों से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने और आधुनिक और कुशल पुलिसिंग के लिए स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रतिष्ठान को मजबूत करने का भी आह्वान किया।

उपायुक्त ने पुंछ में एनएच 144-ए, अन्य सड़क परियोजनाओं पर काम की प्रगति की समीक्षा की

पुंछ

उपायुक्त पुंछ विकास कुंडल ने जिले में सीमा सड़क संगठन द्वारा क्रियान्वित की जा रही सड़क परियोजनाओं पर काम की प्रगति की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में बीआरओ के प्रमुख अधिकारी, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और तहसीलदारों ने भाग लिया। चर्चा जम्मू से पुंछ एनएच 144-ए राजमार्ग, राजौरी थनामंडी सुरनकोट रोड और शाहपुर रोड सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति पर केंद्रित थी, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास के लिए आवश्यक हैं।

उपायुक्त ने जम्मू-पुंछ एनएच 144-ए पर काम की प्रगति पर अपडेट प्राप्त किया। बताया गया कि भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने इन परियोजनाओं की प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए भूमि मुआवजे के समय पर वितरण की तात्कालिकता पर जोर दिया।

संबंधित एजेंसियों को आरटीएस और एनएच 144-ए के संरक्षण के भीतर संरचनाओं को हटाने में तेजी लाने के लिए कहा गया, जिसके लिए भूमि मालिकों को



मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। उपायुक्त ने कहा, बाधाओं को दूर करने और इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं

के सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है।

उपराज्यपाल ने सेना के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की

जम्मू

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अखनूर सेक्टर में ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेना के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल ने कहा मैं हमारी सेना के उन बहादुरों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता हूँ जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनकी वीरता और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा। दुख की इस घड़ी में पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है।”

गुरु रविदास जयंती के अवसर पर उपराज्यपाल की शुभकामनाएं

जम्मू

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरु रविदास जी जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। एक संदेश में, उपराज्यपाल ने कहा, संत गुरु रविदास जी जयंती के शुभ अवसर पर, मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु रविदास जी का जीवन और शिक्षाएं हम सभी के लिए प्रेरणा का स्थायी स्रोत हैं। आइए हम उनके महान मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें और समर्पण और समर्पण के साथ मानवता की सेवा करें।

संपादकीय टैरिफ और कारोबार ट्रंप-मोदी मुलाकात से जगी नई उम्मीदें

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि अमेरिका की नीतियां 'अमेरिका से शुरू होकर अमेरिका' पर ही समाप्त हो जाती हैं। दूसरी बार सत्ता में आए ट्रंप ने जिस आक्रामक तरीके से कनाडा, मैक्सिको व चीन आदि पर टैरिफ लगाए हैं, वैसी आक्रामकता उन्होंने भारत के प्रति नहीं दिखायी। हाल में व्हाइट हाउस में संपन्न प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत कई मायनों में सकारात्मक रही। उसमें किसी तरह की तल्लखी नजर नहीं आई। यह निर्विवाद सत्य है कि अमेरिका हमेशा अपने कारोबारी हितों को ही प्राथमिकता देता है। इस मुलाकात में यही नजर आया कि ट्रंप दोनों देशों के व्यापार संतुलन का पलड़ा अमेरिका के पक्ष में करने को कटिबद्ध है। इस मुलाकात में उन्होंने टैरिफ का मुद्दा भी उठाया और व्यापार घाटे को कम करने के लिये अधिक तेल, गैस और सैन्य साजो-सामान खरीदने की जिम्मेदारी भारत पर डाल दी। दरअसल, भारत कुछ उन देशों में शामिल है जिनके साथ व्यापार का पलड़ा अमेरिका के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही भारत में अमेरिकी सामान पर तर्कसंगत कर लगाने की बात भी कही। यदि ट्रंप की मौजूदा नीतियां सिरे चढ़ी तो व्यापार की परिस्थितियां अमेरिका के अनुकूल भी हो सकती हैं। ट्रंप ने मोदी को अपनी तुलना में बेहतर सख्त वार्ताकार बताया। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने तथा लाभप्रद व्यापार समझौते के लिये बातचीत करने का संकल्प भी जताया। भविष्य में व्यापार समझौता अमेरिका के पक्ष में न झुके, इसमें पीएम मोदी के कूटनीतिक कौशल की परीक्षा भी होनी है। यहां उल्लेखनीय है कि मोदी-ट्रंप मुलाकात में रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में बातचीत सकारात्मक रही। दोनों देशों ने एक दस वर्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। जिसमें प्रमुख हथियारों और प्लेटफार्मों के सह-उत्पादन को आगे बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना का मार्ग प्रशस्त किया गया। वहीं दूसरी ओर यदि भारत को अमेरिकी एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की प्रस्तावित आपूर्ति परवान चढ़ती है तो पड़ोसी देशों की बेचैनी और बढ़ जाएगी।

इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण घोषणा यह भी रही है कि 26/11 के साजिशकर्ता तहव्युर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी गई है। यह पाकिस्तान को चेतावनी भी है कि वह अपनी जमीन से आतंकवादियों को सीमापार आतंकी हमलों को अंजाम देने में मदद बंद करे। अब इस्लामाबाद पर मुंबई और पठानकोट के आतंक हमलों के साजिशकर्ताओं को सजा देने का दबाव भी बढ़ जाएगा। निस्संदेह, ट्रंप का 'टैरिफ आतंकवाद' निगलने वाली कड़वी गोली हो सकती है, लेकिन भारत की रक्षा तैयारियों में अमेरिका की बड़ी भूमिका एक आकर्षक प्रस्ताव होगा। हालांकि, ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को लेकर कोई सीधी घोषणा तो नहीं की लेकिन यह जरूर कहा कि जितना टैरिफ अन्य देश अमेरिकी सामान पर लगाते हैं, अमेरिका भी उसी अनुपात में टैरिफ लगाएगा। उल्लेखनीय है कि जिस समय पीएम मोदी अमेरिका यात्रा के लिये निकले, अमेरिका से अपमानजनक तरीके से भारत भेजे गए कथित अवैध प्रवासियों का मुद्दा गर्म था। ट्रंप के साथ मुलाकात में भारत ने अवैध रूप से आए भारतीयों को वापस लेने की बात भी कही। पत्रकार वार्ता में मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर हमारे विचार एक जैसे हैं। यदि अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों की पुष्टि होती है तो हम उन्हें वापस लेने के लिये तैयार हैं। उन्होंने इसे मानव तस्करी की करतूत बताया। कहा कि तब नहीं मालूम होता कि उन्हें अमेरिका ले जाया जा रहा है। ये बहुत आम परिवारों के बच्चे हैं, जिन्हें बड़े सपने दिखाए जाते हैं और बड़े-बड़े वायदे किए जाते हैं। उन्होंने भोले लोगों को इस साजिश से बचाने हेतु मानव तस्करी पर शिकंजा कसने की बात कही। पिछले दिनों भारतीय विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत व अमेरिका यह तय करने का प्रयास कर रहे हैं कि वापस भेजने की प्रक्रिया के दौरान किसी भारतीय नागरिक के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने दुनिया में इस्लामी चरमपंथ के खतरे से निपटने के लिये भारत और अमेरिका के मिलकर काम करने की भी मंशा जाहिर की। ट्रंप ने नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र सहयोग में प्रगति की बात भी कही।

मुख्य संपादक
विवेक धल्लम

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक विवेक धल्लम (गली नं. 1, वॉर्ड नं. 12, नजदीक एगो पेट्रोल पंप व तहसील, बाड़ी ब्राह्मणा, जम्मू व कश्मीर 181133) द्वारा शिवम् आफसेट प्रिंटिंग प्रेस, फत्वा चौक (नजदीक जेएडके बैंक) ग्रेटर कैलाश, जम्मू (जम्मू-कश्मीर) से प्रकाशित।

संपादक
विवेक धल्लम

फोन- 9419180421, ईमेल: admin@jammunewsmission.com
नोट: इस अंक में प्रकाशित सामग्री से संपादक प्रकाशित का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

प्राप्त स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जाएगा। सभी विवादों का निपटारा जम्मू संभाग की सीमा के अंतर्गत आने वाली सक्षम न्यायालयों व फोरमों में ही किया जाएगा।

भारत एआई क्रांति में अग्रणी बन दुनिया का नेतृत्व करे

ललित गर्ग

एआई को लेकर भारत की सोच सकारात्मक एवं विकासमूलक है इसीलिये प्रधानमंत्री मोदी ने यह सही कहा कि इस तकनीक में दुनिया को बदलने की ताकत है, लेकिन अमेरिका की कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियों ने सूचना संसार में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है।

पेरिस में हुए दो दिवसीय एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) एक्शन समिट ने जहां दुनिया के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के महत्व को उजागर किया, वहीं यह भी साफ कर दिया कि इस मामले में होड़ के बावजूद सभी देशों का आपसी तालमेल बनाए रखते हुए सावधानी से आगे बढ़ना जरूरी है। एआई से बदलती दुनिया के चमत्कार वरदान से कम नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी चुनौतियां एवं खतरे इसे अभिशाप में भी बदल सकते हैं। बहुत आवश्यक है कि इसके उपयोग के संदर्भ में कोई वैश्विक ढांचा एवं नियंत्रण का केन्द्र एवं नीति बने। क्योंकि एआई के दुरुपयोग के खतरे किसी से छिपे नहीं। अभी एआई का उपयोग अपने प्रारंभिक चरण में ही है, लेकिन उससे पैदा होने वाली कई चुनौतियों एवं खतरों ने सिर उठा लिया है। लेकिन इस नई तकनीक से जीवनशैली, शिक्षा, चिकित्सा, युद्ध, सेना, शासन-प्रशासन, चुनाव, व्यापार, विचार आदि में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भारत एआई को लेकर बहुत उत्साहित है और दुनिया में एआई का सबसे बड़ा केन्द्र बनने को भी तैयार है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर बैठक की सह-अध्यक्षता की बल्कि अगली शिखर बैठक की मेजबानी करने की पेशकश भी करते हुए बता दिया कि भारत इस पहल को कितनी गंभीरता से लेता है।

भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होते हुए तकनीकी विकास की दृष्टि से भी सफलता के नये झंडे गाड़ रहा है। एआई को लेकर भारत की सोच सकारात्मक एवं विकासमूलक है इसीलिये प्रधानमंत्री मोदी ने यह सही कहा कि इस तकनीक में दुनिया को बदलने की ताकत है, लेकिन अमेरिका की कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियों ने सूचना संसार में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है। उनके एकाधिकार और उनकी मनमानी से निपटना विश्व के तमाम देशों के लिए मुश्किल हो रहा है। यदि इसी तरह का एकाधिकार एआई कंपनियों ने भी स्थापित कर लिया तो फिर समस्या गंभीर हो जाएगी। सबसे अधिक समस्या विकासशील और निर्धन देशों को होगी, जो पहले से ही चुनिंदा तकनीकी कंपनियों के वर्चस्व तले दबी हुई है। मोदी ने एआई तकनीक के संतुलित एवं विवेकसम्मत उपयोग एवं विकास की आवश्यकता को भी

व्यक्त किया। क्योंकि यह उन्नत तकनीक बनाने वाली कुछ कंपनियां उसे अपने हिसाब से संचालित करती हुई भी दिख रही हैं। इस तकनीक का मनमाना इस्तेमाल न होने पाए, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रभावी कदम उठाने होंगे। यह एआई एक्शन समिट ऐसे समय हो रही है, जब चीनी कंपनी डीपसीक दुनिया को एक जबर्दस्त झटका दे चुकी है।

भारत एआई की चुनौतियों एवं खतरों को लेकर सतर्क है। क्योंकि एआई द्वारा प्रस्तुत चुनौतियां बहुआयामी हैं और लगातार विकसित हो रही हैं। उदाहरण के लिए डीपफेक, जो डिजिटल मीडिया हैं-वीडियो, ऑडियो और चित्र-जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके संपादित और हेरफेर किया जाता है, हाइपर-रियलिस्टिक डिजिटल मिथ्याकरण को शामिल करते हैं। इसका संभावित रूप से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, सबूत गढ़ने और लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास को कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जबकि डीपफेक का इस्तेमाल चुनावों जैसे कुछ मामलों में किया गया है, उनका उपयोग विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से देखा जा रहा है। डीपफेक के अलावा, एआई से जुड़े अन्य जोखिम भी हैं। इनमें गोपनीयता, पूर्वाग्रह, पारदर्शिता, जवाबदेही और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए एआई के संभावित दुरुपयोग से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। भारत सरकार इन मुद्दों को सलाह और विनियमों के माध्यम से नियोजित एवं नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है जो पारदर्शिता, सामग्री मॉडरेशन, सहमति तंत्र और डीपफेक पहचान पर जोर देते हैं ताकि जिम्मेदार एआई तैनाती सुनिश्चित हो और चुनावी अखंडता की रक्षा हो सके। यह एक सतत प्रयास है और जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, इन चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक मनबूत तंत्र के विकास के साथ सक्षम होने की अपेक्षा रहेगी। एआई विकसित होता रहेगा, नये-नये करिश्माई एवं चमत्कारी आयाम उससे जुड़ते रहेंगे और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह ऐसे तरीके से हो जो सभी के लिए सुरक्षित, नैतिक और लाभकारी हो। आवश्यक बुनियादी ढांचे, हार्डवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमताओं के विकास में सहायता के लिए निवेश महत्वपूर्ण है। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग से आवश्यक पूंजी जुटाई जा सकती है। यह संयुक्त प्रयास एआई नवाचार, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकेगा और जिससे भारत एआई क्रांति में अग्रणी बन दुनिया का नेतृत्व कर सकेगा।

इसी पहलू को रेखांकित करती है यह पेरिस की तीसरी एआई एक्शन समिट, जिसमें दुनिया भर के 90 देशों और तमाम बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस हमारे भविष्य का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन किसी भी वजह से इसकी ग्रोथ को बेकाबू होने दिया गया तो उसके परिणाम खतरनाक साबित हो सकते हैं। भारत की भूमिका को ख़ास बनाता है इसका असाधारण टैलेंट पूल, इसके वे इंजिनियर और वैज्ञानिक जो नाम मात्र की लागत पर बड़े-बड़े अंतरिक्ष अभियान को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अभी

तक इस मामले में भारत की पहल बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। बेहतर होगा कि केन्द्र सरकार एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाकर इस तकनीक को लेकर अपनी प्राथमिकता तय करे। इनोवेशन में भारत को हर जोखिम को उठाने के लिये स्वयं को सक्षम करना होगा। एआई का समुचित लाभ उठाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। एआई के जरिये वे अनेक काम किए जा सकते हैं, जो अब तक मनुष्य करते रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि उसमें मानवीय संवेदनाएं नहीं होतीं और वह उपलब्ध डाटा के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचती है। अब यदि डाटा ही सटीक न हो तो नतीजे भी नुकसान पैदा करने वाले हो सकते हैं। इस पर हैरानी नहीं कि अति उन्नत एआई को मानव सभ्यता के लिए संकट के रूप में भी देखा जा रहा है। इस आशंका को निर्मूल साबित करने वाले उपाय करना समय की मांग है और उन पर ज्यादा फोकस करना होगा।

इस तरह की तकनीक तभी लाभकारी सिद्ध होती है, जब उसका उपयोग समझदारी, नैतिकता एवं विवेकपूर्ण होता है। ज्यादा जरूरी है उसके दुरुपयोग की आशंकाओं पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाने की स्थितियों एवं तंत्र को विकसित करने की। एआई के मामले में ऐसा इसलिए अनिवार्य रूप से करना होगा, क्योंकि यह मानव जीवन को कहीं गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। एआई एक नई तकनीक है और बहुत से लोग उसके प्रयोग के तौर-तरीकों से अपरिचित हैं। इसीलिए यह आशंका उभरी है कि उसके कारण रोजगार का संकट पैदा हो सकता है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नौकरियों पर एआई के प्रभाव को समझने के लिए एक व्यापक, डेटा-समर्थित अध्ययन आवश्यक है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है कि एआई दुनिया भर में लगभग 40 प्रतिशत नौकरियों को प्रभावित करेगा, कुछ को प्रतिस्थापित करेगा और दूसरों को पूरक करेगा। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एआई अपने उपयोग के विकास के साथ नए प्रकार की नौकरियां भी पैदा करेगा। एआई पहले से ही विनिर्माण से लेकर बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा तक सभी क्षेत्रों में बदलाव ला रहा है। उदाहरण के लिए, शिक्षा क्षेत्र में, एआई व्यक्तिगत पाठ्यक्रम, परीक्षण, सीखने के तरीके और वितरण को सक्षम करके भारत के सीखने के परिदृश्य को बदल रहा है। निःसंदेह यह नई तकनीक अवसर बन रही है, तकनीकी विकास का सूरज बनकर नयी समाज संरचना को बल दे रही है। यह संभावनाभरा है कि पेरिस शिखर सम्मेलन में एआई के क्षेत्र में भारत और प्रमुख देशों के बीच सामंजस्य बढ़ने के संकेत मिले, लेकिन बात तब बनेगी, जब यह मंच एआई के नियमन एवं नियोजित विकास के लिए सहमति कायम करने की बुनियाद बने। एआई की तीव्र प्रगति और व्यापक अनुप्रयोग को देखते हुए, भारत के लिए अपना स्वयं का एआई सुरक्षा संस्थान स्थापित करना अपेक्षित है। ऐसा संस्थान सुरक्षित और नैतिक एआई प्रथाओं को विकसित करने, अनुसंधान करने और एआई के उपयोग में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

उपमुख्यमंत्री ने सामाजिक पुनर्जागरण में गुरु रविदास की दूरदर्शी भूमिका पर प्रकाश डाला

युवाओं से संतों की शिक्षाओं का अनुसरण कर संतुष्ट जीवन जीने का आह्वान किया

जम्मू

उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चैधरी ने गुरु रविदास सभा कृष्णा नगर में श्री गुरु रविदास जी के 648वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में संबोधित करते हुए, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में श्री गुरु रविदास जी के दूरदर्शी योगदान पर प्रकाश डाला और कहा कि समतावादी और मानवीय दुनिया बनाने के लिए उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना समय की मांग है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में जब भौतिकवादी गतिविधियों ने हमारे समाज के ताने-बाने को तहस-नहस कर दिया है, तब संतुष्ट और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमारे संतों की शिक्षाओं का अनुसरण करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा, “हमें अपने जीवन को अधिक आध्यात्मिक बनाने के लिए अपने संतों और सूफियों की शिक्षाओं का पालन करने की आवश्यकता है, जिससे हमें संतोष और आनंदमय जीवन जीने में मदद मिलेगी।”

उपमुख्यमंत्री ने कहा, “मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज सुनिश्चित करने में गुरु रविदास जी के योगदान से उपमहाद्वीप के लोग अवगत हैं और हमें मानवता की भलाई के लिए इन सिद्धांतों का प्रचार करने की आवश्यकता है।” उन्होंने कहा कि यह हमारी दुनिया को अधिक समावेशी बनाने का आधार बनेगा।

उपमुख्यमंत्री ने युवाओं से महान संतों की आध्यात्मिक शिक्षाओं का पालन करने और अपने भविष्य और स्वास्थ्य



के लिए हानिकारक प्रवृत्तियों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने मादक द्रव्यों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया।

इससे पहले उपमुख्यमंत्री ने आश्रम में मल्था टेका और देश और विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत

भी की।

अखिल जम्मू-कश्मीर श्री गुरु रविदास सभा के प्रबंधन ने भी उपमुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें रोजगार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के उचित क्रियान्वयन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और अन्य संबंधित मांगों जैसे कई मुद्दों को रखा गया।

इससे पहले, पूर्व बीडीसी, सरपंचों और पंचों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपने-अपने क्षेत्रों के कई विकासात्मक मुद्दों को रखा और तत्काल निवारण की मांग की।

उपमुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को उनके मुद्दों और चिंताओं पर विचार करने और उनके शीघ्र निवारण का आश्वासन दिया।

स्वास्थ्य मंत्री ने आईजीजीडीसी में वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित किया, अस्पताल में सीबीसीटी का उद्घाटन किया

सरकार दंत चिकित्सकों की रोजगार संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक संरचित नीति पर काम कर रही है

जम्मू

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण एवं शिक्षा मंत्री सकीना इतू ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार दंत चिकित्सकों की रोजगार संबंधी चिंताओं को दूर करने और सरकारी एवं संबद्ध क्षेत्रों में उनके लिए रोजगार की संभावनाओं का विस्तार करने के लिए एक संरचित नीति पर सक्रिय रूप से काम कर रही है।

मंत्री ने यह बात इंदिरा गांधी सरकारी डेंटल कॉलेज, जम्मू में वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए की।

सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने समाज पर चिकित्सा शिक्षा के महत्वपूर्ण महत्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में दंत चिकित्सा पेशेवरों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, चिकित्सा एक बहुत ही महान पेशा है क्योंकि यह सीधे तौर पर जन कल्याण को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि समाज की भलाई को आकार देने में चिकित्सा पेशेवरों की बहुत सक्रिय भूमिका है।

मंत्री ने आगे कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में हर दूसरे दिन नई तकनीकें आ रही हैं और चिकित्सा पेशेवरों को इन उभरती हुई तकनीकों के अनुसार खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, “चिकित्सा और दंत चिकित्सा क्षेत्र एक



निरंतर विकसित होने वाला क्षेत्र है, जिसमें रोगी देखभाल को बढ़ावा देने के लिए नई प्रगति की आवश्यकता है।” मंत्री ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में दंत चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि सरकार रोजगार संबंधी चिंताओं को दूर करने और दंत चिकित्सकों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक संरचित नीति पर सक्रिय रूप से काम कर रही है।

आईजीजीडीसी की अकादमिक और नैदानिक उत्कृष्टता की सराहना करते हुए उन्होंने छात्रों को समर्पण के साथ ज्ञान प्राप्त करने और करुणा के साथ समाज की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने दंत चिकित्सा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने में संस्थान की भूमिका की भी सराहना की।

अपने स्वागत भाषण में, आईजीजीडीसी की प्रिंसिपल और डीन, डॉ. परवीन अख्तर लोन ने पावरपॉइंट

प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पूरे शैक्षणिक वर्ष में कॉलेज के विभागीय अवलोकन और उपलब्धियों का विवरण दिया गया, जिसमें प्रमुख मील के पथर और विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्होंने छात्रों के बीच शैक्षणिक और पाठ्येतर विकास को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने में मंत्री के हस्तक्षेप की मांग की। संकाय चयन की निष्पक्ष प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए रजिस्ट्रार के लिए लिखित परीक्षा शुरू करने में सरकार की मदद की भी सराहना की।

इस अवसर पर, मंत्री ने कॉलेज के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया जो विभिन्न सरकारी विभागों में विभिन्न क्षमताओं के तहत समाज की सेवा कर रहे हैं। मंत्री ने विभिन्न बैचों के मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया। मंत्री ने कॉलेज पत्रिका ‘उम्मीद’ के पहले संस्करण का भी विमोचन किया, जो छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

इससे पहले, मंत्री ने अस्पताल में डेंटल कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी का उद्घाटन किया।

इसके उपरांत, उन्होंने मरीजों को प्रदान की जा रही दंत चिकित्सा सेवाओं के कामकाज का आकलन करने के लिए अस्पताल का विस्तृत दौरा किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत की और इस सुविधा में प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में प्रतिक्रिया ली।

परीक्षा केंद्रों के आसपास छात्रों के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करें-सकीना इतू

10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षाओं की आगामी बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया

जम्मू

शिक्षा, समाज कल्याण और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इतू ने आज नागरिक सचिवालय में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं की आगामी बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा, शांतमनु, अध्यक्ष जेकेबोस, स्कूल शिक्षा निदेशक, कश्मीर/जम्मू, सभी जिलों के उपायुक्त और एसएसपी, परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, विशेष सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव जेकेबोस, एसएसपी ट्रैफिक ग्रामीण/राष्ट्रीय राजमार्ग, एसएसपी ट्रैफिक शहर श्रीनगर/जम्मू, सभी जिलों के सीईओ और अन्य संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने सभी उपायुक्तों को परीक्षा केंद्रों के अंदर और आसपास छात्रों के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों पर उचित प्रकाश व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और हीटिंग जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं स्थापित करने के लिए कहा।

मंत्री ने कहा “हमारा प्राथमिक उद्देश्य एक सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। विभाग, जिला प्रशासन और अन्य हितधारकों को यह सुनिश्चित करने



के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है कि हमारे युवा छात्रों के सर्वोत्तम हितों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद हों।”

मंत्री ने आगे उपायुक्तों और एसएसपी से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के अंदर और आसपास सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित किए जाएं। उन्होंने उन्हें परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त कर्मियों को तैनात करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि छात्रों और कर्मचारियों के अलावा किसी को भी परीक्षा

केंद्रों के अंदर जाने की अनुमति न हो। उन्होंने एसएसपी से किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल फ्लाइंग स्कॉर्ड के गठन के लिए भी कहा।

परीक्षा प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए अन्य उपायों की समीक्षा करते हुए, सकीना इतू ने उपायुक्तों और सीईओ से परीक्षा प्रक्रिया की उचित निगरानी के लिए अपने-अपने जिलों में संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने

सीईओ को पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने ग्राउंड स्टाफ के साथ लगातार संपर्क में रहने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान, मंत्री ने उपायुक्तों और एसएसपी से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सुरक्षा बलों के काफिले की आवाजाही के दौरान राजमार्गों पर छात्रों की सुविधा हो। उन्होंने उन्हें संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि इस काफिले की आवाजाही के दौरान छात्रों के

एडमिट कार्ड को पास माना जाए।

बैठक के दौरान सकीना इतू ने एसईडी के अधिकारियों को परीक्षाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मंडल और जिला स्तर पर निरीक्षण दस्ते बनाने का भी निर्देश दिया।

बैठक के दौरान, जेकेबोस की अध्यक्षता में मंत्री को परीक्षाओं की तैयारियों के साथ-साथ इन बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए भेजी गई सामग्री की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी।



FIND YOUR PERFECT
WEDDING MAKEUP
LOOK

BOOK AN APPOINTMENT NOW TO AVAIL AMAZING OFFERS

BOOK NOW

☎ 8082520701 | 9055520701 📍 H.O.: BARI BHARAMNA B.O.: GANDHI NAGAR



यशा मुद्गल ने जम्मू और कश्मीर में प्रमुख राजमार्गों के किनारे सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की

जम्मू

आयुक्त सचिव पर्यटन, यशा मुद्गल ने जम्मू और कश्मीर में प्रमुख राजमार्गों और सड़कों के किनारे सुविधाओं और शौचालय सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए नागरिक सचिवालय, जम्मू में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य स्थानीय यात्रियों की बढ़ती जरूरतों और केंद्र शासित प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या को पूरा करना था।

बैठक में आरएंडबी सचिव, एनएचआई, बीआरओ, एनएचआईडीसीएल, आरएंडबी और पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यात्रा के अनुभवों को बेहतर बनाने और प्रमुख मार्गों पर आवश्यक सुविधाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर चर्चा हुई।

बैठक के दौरान बुनियादी ढांचे में सुधार में तेजी लाने के लिए प्रमुख निर्देश जारी किए गए। बीकन अधिकारियों को एक महीने के भीतर सड़क किनारे सुविधाओं के लिए एक स्थान योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। एनएचआई यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जून 2026 तक सभी सुविधाएं कार्यात्मक हो जाएं।

एनएचआईडीसीएल को सोनमर्ग में एक



शौचालय परिसर के लिए प्राथमिकता परियोजना के साथ, सोनमर्ग सुरंग और जोजिला सुरंग के बीच एक सड़क के किनारे सुविधा परिसर विकसित करने का काम सौंपा गया।

इसके अलावा, काजीगुंड, मरहमा और जज्जर कोटली में सार्वजनिक सुविधाओं को अप्रैल 2025 तक चालू किया जाना है। दृश्यता और पहुंच बढ़ाने के लिए, कार्यान्वयन एजेंसियों को शौचालय सुविधाओं को चिह्नित करने और राजमार्गों के साथ दूरी का संकेत देने वाले नए साइनबोर्ड स्थापित करने का भी

निर्देश दिया गया है।

गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, पटनीटॉप, सनासर, भद्रवाह और दूधपथरी सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों में सुविधाओं में सुधार पर विशेष जोर दिया गया, जहां पर्यटकों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सड़क किनारे सुविधाएं आवश्यक हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, आर एंड बी के मुख्य इंजीनियरों को रणनीतिक स्थानों पर शौचालय परिसरों और पार्किंग स्थानों के लिए अवधारणा योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अतिरिक्त, आर एंड बी और पर्यटन विभागों को प्रमुख राजमार्गों के किनारे नई सुविधाओं के लिए स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए एक अंतर विश्लेषण करने के लिए कहा गया था। यह एक सर्वांगीण बुनियादी ढांचा विकास योजना सुनिश्चित करेगा जो निवासियों और आगंतुकों दोनों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगी। जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्व पर जोर देते हुए यशा मुद्गल ने आधुनिक और सुव्यवस्थित सुविधाओं के माध्यम से यात्रा अनुभवों को बढ़ाने के लिए

सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पर्यटन विकास एजेंसियों के सीईओ को केवल बाधा-मुक्त भूमि पर सुविधाओं का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया, जहां वन विभाग से सभी आवश्यक मंजूरी समय पर प्राप्त की जा सके। यह पहल जम्मू-कश्मीर के पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, यात्रियों के लिए एक बाधा रहित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जबकि इस क्षेत्र को देश भर और विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए एक शीर्ष स्तरीय गंतव्य के रूप में बढ़ावा देता है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोनमर्ग का दौरा किया, आग से हुए नुकसान का आकलन किया

प्रभावित दुकानदारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की, सीएमआरएफ के तहत सहायता स्वीकृत की

सोनमर्ग (गांदरबल)

हाल ही में पुराने बाजार सोनमर्ग में हुई विनाशकारी आग की घटना के मद्देनजर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नुकसान का जायजा लेने और प्रभावित दुकानदारों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रभावित स्थल का दौरा किया।

मुख्यमंत्री के साथ उनके सलाहकार नासिर असलम वानी, विधान सभा सदस्य कंगन मियां मेहर अली और गांदरबल के उपायुक्त जितन किशोर भी थे। अपनी यात्रा के दौरान, मुख्यमंत्री ने सोनमर्ग मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बातचीत की, अपनी सहानुभूति व्यक्त की और उन्हें सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

उन्होंने प्रभावित व्यापारियों की सहायता करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित उपाय सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बाद में सीएम ने सोनमर्ग मार्केट एसोसिएशन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें डीसी, एसएसपी, एसडीएम कंगन, सीईओ सोनमर्ग विकास प्राधिकरण और अन्य जिला अधिकारियों सहित वरिष्ठ



अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में व्यापारियों की चिंताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिन्होंने तत्काल वित्तीय सहायता, भवन पुनर्निर्माण की अनुमति और सोनमर्ग में एक अग्निशमन सेवा स्टेशन की स्थापना जैसी प्रमुख मांगें रखीं। इन चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दुकानों

के पुनर्निर्माण को एक सुनियोजित डिजाइन का पालन करना चाहिए, जिसे पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और एसडीए सहित सभी हितधारकों के परामर्श से विकसित किया गया है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि यह दृष्टिकोण सुरक्षा बढ़ाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकेगा। सोनमर्ग में बढ़ते पर्यटन प्रवाह

पर प्रकाश डालते हुए, विशेष रूप से सुरंग के उद्घाटन के बाद, सीएम ने क्षेत्र में एक स्थायी अग्निशमन सेवा स्टेशन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया।

उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि एक स्थायी फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए संबंधित हितधारकों

के परामर्श से इसके स्थान को अंतिम रूप दिया जाएगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रभावित दुकानों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी गई है, जो इस कठिन समय के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को कुछ सहायता प्रदान करेगी।

उपराज्यपाल ने स्काउट्स और गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स को जम्मू-कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए

एलजी ने राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने और समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए जम्मू-कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की सराहना की

जम्मू-कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स यह सुनिश्चित करने के मिशन पर है कि स्वयं से पहले दूसरों की सेवा करना समाज का आदर्श वाक्य है-एलजी सिन्हा

प्रगतिशील समाज और समृद्ध राष्ट्र विकसित करने के लिए युवा ही एकमात्र शक्ति है-एलजी सिन्हा

युवाओं के माध्यम से हम परिवर्तन की लौ जला सकते हैं-एलजी



जम्मू

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कन्वेंशन सेंटर में जम्मू-कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के राज्य पुरस्कार समारोह में भाग लिया।

उपराज्यपाल ने स्काउट्स एंड गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स को जम्मू-कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए और सभी प्राप्तकर्ताओं को अपनी

शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ये प्रमाणपत्र उनके समर्पण, निस्वार्थ सेवा, कड़ी मेहनत और अनुशासन की मान्यता हैं।

उपराज्यपाल ने सामुदायिक सेवाओं और राष्ट्र निर्माण की दिशा में भारत स्काउट्स और गाइड्स आंदोलन से जुड़े सभी लोगों के अनुकरणीय योगदान की सराहना की।

उपराज्यपाल ने कहा जम्मू-कश्मीर भारत स्काउट्स और गाइड्स यह सुनिश्चित करने के

मिशन पर है कि स्वयं से पहले दूसरों की सेवा करना समाज का आदर्श वाक्य है। इस दृष्टिकोण के साथ जम्मू-कश्मीर भारत स्काउट्स और गाइड्स राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने और समाज की बेहतरी के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने में सराहनीय काम कर रहे हैं।

उपराज्यपाल ने स्काउट्स और गाइड्स से जमीनी स्तर पर 'परिवर्तन के एजेंट' के रूप में कार्य करने और युवाओं को समाज और राष्ट्र के रचनात्मक परिवर्तन के लिए खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा एक प्रगतिशील समाज और एक समृद्ध राष्ट्र विकसित करने के लिए युवा ही एकमात्र शक्ति है जो आज हमारे पास है। युवाओं के माध्यम से हम परिवर्तन की लौ जला सकते हैं। उपराज्यपाल ने कहा, स्काउट्स और गाइड्स को सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से निपटने का काम सौंपना महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें नवीन समाधान प्रदान करने की क्षमता है।

उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर भारत स्काउट्स और गाइड्स से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों

पर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में भी काम करने को कहा।

उपराज्यपाल ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर भारत स्काउट्स और गाइड्स विभिन्न क्षेत्रों में युवा नेताओं का एक नेटवर्क बनाएं, युवाओं को सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं से जोड़ें और स्काउट्स और गाइड्स को एक समर्पित टीम बनाएं जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करें।

उपराज्यपाल, जो जम्मू-कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के मुख्य संरक्षक भी हैं, ने जम्मू-कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, वार्षिक अनुदान सहायता के साथ-साथ उन्हें जिस भी प्रकार की सहायता और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी, वह निश्चित रूप से प्रदान की जाएगी। उन्होंने आगामी राष्ट्रीय एकता शिविर के सुचारू संचालन के लिए सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया।

HELP LINE

Important Telephone Nos.

Civil Secretariat	2547365-69
Jammu University	2435259,2435248
RRL, Jammu	2544382, 2549051
Army	2432453, 2432653
Municipality Jn. Lines	2578503, 18001803333
Passport Office	2433359

Postal Services

H.P.O. City	2543606
Gandhi Nagar	2435863

Fire Services

City	2544263
Gandhi Nagar	2457705
Canal	2554064
Gangyal	2480026

Cooking Gas dealers

Chenab Gas	2547633
Gulmoure Gas	2430835
H.P. Gas	2578456
Jakfed	2548297
Shivangi Gas	2577020
Tawi Gas	2548455

Power House

Gandhi Nagar	2430180
Canal Road	2554147
Janipur	2533359
Nanak Nagar	2430776
Parade	2542289
Satwari (Jammu Cantt.)	2452813

City Hospitals

G.M.C Jammu	2584290, 91. 94, 2584211, 25
GMC Causality	2575364
S.M.G.S. Jmu	2547635, 258477
Govt. Hosp. G. Nagar	2430041,2431740
Dental Hospital Jmu	2544670
Psychiatric Disease Hos.	2577444
Ascoms Sidhra	262251, 262267, 262536, 39
B.N. Charitable	2555631, 2505310
Vivekanand Hospital	2547418
G.B. Pant Hosp. Satwari	2433500
Military Hospital Sat.	2435572

Police Station, Jammu City

Bagh-e-Bahu	2459777
-------------	---------

Bakshi Nagar	2580102
Bus Stand	2566499
City	2543688
Gandhi Nagar	2430528
Gangyal	2481204
Nowabad	2565274
Pacca Danga	2448610
Railway Station	2472870
Saink Colony	2468666
Satwari	2430364
Channi Himmat	2465164
Transport Nagar	2475444
Trikuta Nagar	475133, 2470679
G. Nagar	2459660
S.S.P. City	2547807
S.P. South	2433778
SSP TRAFFIC JAMMU	0191-2578774
Police Control Room	100

Airlines

Air Port	2450520,21,2430449
Indian Airlines	2574312
Spice Jet	2431887
Go Air	2435668
Kingfisher	2432651
Jet Airways	2453999

Railways

Railway Enquiry	131,132,2476407
Booking	2470318
Reservation	2470315

Telecom Department

Directory Enquiry	197
Fault Repair	180
Billing Complaint	2543896
Trikuta Nagar Exchange	2470000

Raj Bhawan Jammu

H.E THE GOVERNOR, J&K	2560225
PVT. SECY. TO H.E.G	
2544939/2560225/2452201	

CHIEF MINISTER'S SECRETARIAT JAMMU

CM	2546766/2560203
PRINCIPAL SECY. TO C.M	2544017/2542159
ADVISOR TO C.M	2560239
PVT. SECY. TO C.M	2546466/2540421

CREMATION-SMITI SERVICES JAMMU

SEWA-SAMITI (HEAD OFFICE) 2573905

COURIER SERVICE

BLUE DART	2432806
DHL	94191-90329
AHL	94191-90329
LINKER COURIER	94191-88398
JUST CALL INFO	2476060
NATIONAL HELP DESK CALL	094192-22222
FAROOQ JI (SECRETARY TO ADGP)	9149598407
CHIEF ENGINEER PWD JAMMU	0191-2471788
CHIEF ENGINEER PHE JAMMU	0191-2547586, 2544356
CHIEF ENGINEER PDD JAMMU	0191-2545061
DC OFFICE JAMMU	0191-2544366
RAILWAY ENQUIRY	1800111321
AIRPORT ENQUIRY JAMMU	0191-2437843
ISBT ENQUIRY JAMMU	0191-2435262
RTO JAMMU	0191-2472490
SHARAT CHANDER KHAJURIA	9419127999
AN INTERNATIONAL ACADEMIC SCHOLAR	
PROF. (DR.) KESHAV SHARMA	9469211211
VICE-CHANCELLOR THE ICFAI	
UNIVERSITY HIMACHAL PRADESH	
SANJAY GANDOTRA	6006619429
DEFENCE BUSINESS CONSULTANT	
ANIL KAPAH	9419199999
BUSINESS TYCOON AND SECRETARY AMAR SINGH CLUB	
KULDEEP KAUL	9811156926
INTERNATIONAL BUSINESS TYCOON	
BHUPINDER SINGH (IAS)	94190112477
COMMISSIONER HEALTH SERVICES	
BRIJ MOHAN SHARMA	9419144300
CHIEF CONSERVATOR FOREST UDHAMPUR	
S. OPINDERJEET SINGH (KAS)	9419019026
FINANCE DIRECTOR PDD	
DR. ASHOK VAID (ONCOLOGIST)	9810212235
DIRECTOR MADANTA HOSPITAL	
DR. KULBUSHAN GUPTA HOD RADIOLOGY	9419190360
GROUP CAPT. KULOWANT SINGH	7889794904
COL PRITHVIRAJ	9419281250
DR. RAJESH SINGH (VET DOCTOR, CAMEL EXPERT, WORKING WITH SHEIKHS) DUBAI	+971567237345
COL. BRIJ BHUSHAN SINGH	8130702061

उपमुख्यमंत्री ने जम्मू को और अधिक विकसित बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की अपील की

जम्मू जिले की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच समन्वय का आह्वान किया

जम्मू

उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने अधिकारियों को जम्मू जिले के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि लोगों को फायदा हो और यह सभी बुनियादी और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण देश के सबसे विकसित शहरों में से एक बन सके।

उपमुख्यमंत्री ने ये निर्देश जम्मू जिले की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए दिये।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सतीश शर्मा भी उपस्थित थे।

बैठक में जिला विकास परिषद के अध्यक्ष भारत भूषण, जिला विकास परिषद के उपाध्यक्ष सूरज सिंह, जम्मू जिले के विधायक शाम लाल शर्मा, विक्रम रंधावा, मोहन लाल भगत, अतुल गुप्ता, राजीव कुमार, धारू राम भगत, नरिंदर सिंह रैना, अरविंद गुप्ता, सुरेंद्र कुमार भी शामिल हुए।

जिला विकास आयुक्त सचिन कुमार वैश्य और विभागों के प्रमुख, क्षेत्रीय अधिकारी भी बैठक में भौतिक और आभासी मोड में शामिल हुए।

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न



योजनाओं के निर्माण, उनकी निगरानी और कार्यान्वयन में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जमीनी स्तर के लोग भी इसमें शामिल हों, जिससे योजना कार्यान्वयन के अलावा शासन की प्रभावशीलता में सुधार होगा।

विधायकों द्वारा पेश की गई मांगों का जवाब देते हुए, उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पहले से शुरू की गई पहलों को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया ताकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे हो जाएं और लोगों को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी उचित परामर्श किया जाना चाहिए ताकि यदि कोई बाधा हो तो उसे दूर किया जा सके और विकासात्मक पहल स्थानीय मांगों और जरूरतों के अनुरूप हो।

उपमुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों और

निष्पादन एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे कार्यान्वयन में तेजी आएगी और पहल व्यापक हो जाएगी।

जम्मू के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि यह क्षेत्र देश में सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक के रूप में उभरे। उन्होंने कहा, हमें सरकार के विकासात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी संबद्धताओं की परवाह किए बिना अपने सभी प्रयासों को समर्पित करना चाहिए ताकि जम्मू देश के सबसे विकसित और मांग वाले क्षेत्रों में से एक बन जाए और लोग विकासात्मक योजनाओं से लाभान्वित हों।

इससे पहले जिला विकास आयुक्त, जम्मू

ने विभिन्न क्षेत्रों के तहत की गई विभिन्न विकासात्मक पहलों का संक्षिप्त विवरण दिया।

बैठक में बताया गया कि जम्मू जिले के लिए कैपेक्स के तहत अनुमोदित परिव्यय 127.76 करोड़ है। यूटी घटक के तहत 3891 कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें से 2261 पूरे हो चुके हैं। इसी प्रकार, जिला कैपेक्स बजट के तहत 3646 कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें से 2046 पूरे हो चुके हैं।

बैठक में यह भी बताया गया कि मनरेगा के तहत श्रम बजट 32.22 करोड़ है, जिसमें से 99.44 प्रतिशतका व्यय दर्ज करते हुए 32.04 करोड़ खर्च किया गया है। 86 हजार जॉब कार्ड जारी किये गये हैं। इसी प्रकार, 14737 कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें से 3931 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

पीएमएवाई-जी क्षेत्र के तहत जिले में 99.59 प्रतिशत पूर्णता दर्ज की गई है, जिसमें 12.09 करोड़ की उपलब्धता में से 12.04 करोड़ व्यय के रूप में दर्ज किए गए हैं।

आईडब्ल्यूएमपी के तहत कुल 60 कार्यों को मंजूरी दी गई है, 55 शुरू किए गए हैं और 30 पूरे हो गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत 48 स्वच्छता परिसरों पर काम शुरू किया गया है, जिनमें से 18 पूर्ण हो चुके हैं, 222 सामुदायिक निर्मित गड्डों पर भी काम शुरू किया गया है, जिनमें से 74 पूर्ण हो चुके हैं। स्वीकृत 17179 इकाइयों में से 14927 आईएचएचएल पूरे हो चुके हैं।

इसी प्रकार, 95 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज करते हुए, 1900 के लक्ष्य में से 1805 एआईपी आईएचएचएल पूरे हो गए हैं।

जल जीवन मिशन के तहत कुल 283 जलापूर्ति योजनाएं शुरू की गई हैं, 78 पूरी हो चुकी हैं और 177 पूरी होने वाली हैं। इसी प्रकार, 70 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज करते हुए 173857 के लक्ष्य में से कुल 121781 घरों को कनेक्शन प्रदान किया गया है।

पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत सड़क लंबाई 868.51 किलोमीटर में से 828.89 किलोमीटर सड़क पूरी हो चुकी है और सभी स्वीकृत 98 बस्तियों को जोड़ा जा चुका है।

डीडीसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित कई मुद्दे उठाए और इनके तत्काल निवारण की मांग की और पीएचई, आर एंड बी, पीडीडी, स्वास्थ्य, आरडीडी और साथ ही अन्य संबंधित क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के अलावा पहले से शुरू की गई परियोजनाओं को बढ़ाने की भी मांग की।

मुख्य सचिव ने अनंत खेल 2025, केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में पदक प्रदान किए

जम्मू

जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की वार्षिक खेल प्रतियोगिता अनंत खेल 2025, 27 जनवरी से 29 जनवरी 2025 तक विश्वविद्यालय परिसर, बागला सुचानी में 19 खेल आयोजनों में 600 छात्रों और 100 संकाय और कर्मचारियों की भागीदारी के साथ उच्च उत्साह के साथ आयोजित की गई थी।

खेल महाकुंभ का समापन आज विश्वविद्यालय परिसर में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सचिव अटल डुल्लू की उपस्थिति में बहुप्रतीक्षित पदक समारोह के साथ हुआ।

अपने संबोधन में, अटल डुल्लू ने एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के उद्भव की सराहना की और छात्रों के लिए विश्वविद्यालय जीवन की विशेषताओं को रेखांकित किया। उन्होंने खेल भावना के महत्व पर प्रकाश डाला जो एक राष्ट्र को महान बनाती है। इस अवसर पर सांबा के उपायुक्त



राजेश शर्मा सम्मानित अतिथि थे।

उपकुलपति प्रोफेसर संजीव जैन ने जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों को शारीरिक रूप से स्वस्थ, नैतिक रूप से ईमानदार और राष्ट्र के लिए एक महान

संपत्ति बनाने के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने छात्रों को खेल भावना की सच्ची भावना अपनाने की सलाह दी।

अपने स्वागत भाषण में, डीपीई की

निदेशक प्रोफेसर वंदना शर्मा ने जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में अनंत खेल के दृष्टिकोण और भावना को साझा किया, जहां सीयूजे के प्रत्येक प्रतिभागी ने सही अर्थों में टीम भावना, आपसी सम्मान,

नैतिक व्यवहार और विनम्रता का प्रदर्शन किया।

जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर यशवंत सिंह ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

समारोह में मुख्य सचिव द्वारा क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो-खो, कबड्डी, भाला फेंक, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, सौंदर्यशास्त्र, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, मैराथन आदि व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में 51 स्वर्ण पदक, 50 रजत और 30 कांस्य पदक प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि द्वारा पदक प्राप्त करने वाले छात्रों और कर्मचारियों की कुल संख्या 400 से अधिक थी।

स्पोर्ट्स मीट की शानदार विशेषता अनंत-खेल-2025 के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अध्ययन के एक स्कूल के लिए समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नई शुरू की गई उपकुलपति की ट्रॉफी थी। यह ट्रॉफी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एजुकेशन ने जीती।

उपराज्यपाल ने कश्मीर घाटी में सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा के लिए श्रीनगर में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

जम्मू-कश्मीर पुलिस और उसकी विभिन्न शाखाओं को एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने और आतंकवाद तथा आतंकवादियों को सहायता देने वालों को कुचलने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश दिया

मैंने जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को बेअसर करने के लिए खुली छूट दे दी है-एलजी सिन्हा

आतंकवाद का समर्थन और वित्तपोषण करने वालों को बहुत भारी कीमत चुकानी होगी-एलजी

उपराज्यपाल ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और एसएसपी को आतंकवाद से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश दिया

श्रीनगर



उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर संभाग में सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा हेतु श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में डीजीपी जम्मू-कश्मीर नलिन प्रभात, एडीजीपी मुख्यालय एम.के. सिन्हा, एडीजीपी सीआईडी नीतीश कुमार, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मंदीप के. भंडारी, आईजीपी कश्मीर विधि कुमार बर्डी, आईजीपी अपराध डॉ. सुनील गुप्ता, आईजीपी सुरक्षा सुजीत कुमार, आईजीपी रेलवे विवेक गुप्ता, रेंज डीआईजी, एसएसपी, एपी/आईआर बटालियन के कमांडेंट और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विभिन्न अन्य वरिष्ठ अधिकारी,

व्यक्तिगत रूप से और वर्चुअल मोड के माध्यम से शामिल हुए।

डीजीपी ने अध्यक्ष को घाटी के वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य और जोनल, रेंज और जिला स्तर पर उग्रवाद, कानून और व्यवस्था, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, आतंकवादी भर्ती आदि जैसी विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार किए गए रोडमैप के बारे में जानकारी दी।

आईजीपी कश्मीर ने कश्मीर क्षेत्र की चुनौतियों और उपलब्धियों तथा भविष्य के लिए रणनीतिक दूरदर्शिता पर प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी।

उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के विभिन्न विंगों के कामकाज का मूल्यांकन किया और विशेष रूप से यूएपीए और एनडीपीएस से संबंधित अपराध संबंधी प्रदर्शन सूचकांकों के संबंध में अपनी संतुष्टि व्यक्त की।

उपराज्यपाल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और इसके विभिन्न विंगों के प्रमुखों को एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने और आतंकवाद और आतंकवादियों को सहायता देने वाले लोगों को कुचलने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश दिया।

उपराज्यपाल ने कहा, माननीय प्रधान मंत्री

श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जम्मू कश्मीर शांति, प्रगति और समृद्धि के युग का गवाह बन रहा है। मुझे जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के लिए आपकी वीरता, प्रभावी, केंद्रित उपायों और बेहतर संस्थागत व्यवस्थाओं पर पूरा भरोसा है। बेहतर खुफिया पीढ़ी, आतंकवाद विरोधी अभियानों में समन्वय और सटीकता भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा चुनौतियों के सभी आयामों में क्षमता और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ 360-डिग्री दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। उपराज्यपाल ने पुलिस

अधिकारियों से आतंक और नार्को-आतंकवाद मामलों में संपत्ति जब्ती की नीति का सख्ती से पालन करने को भी कहा।

उपराज्यपाल ने अधिकारियों को कश्मीर घाटी में सक्रिय विदेशी आतंकवादियों की पहचान करने और उन्हें बेअसर करने के लिए परिणामोन्मुख रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यवस्थित ध्यान देने का आह्वान किया, जो विरोधी ताकतों और आतंकवादियों को समर्थन प्रदान कर रहा है।

उपराज्यपाल ने कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए आपको जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। मैंने जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को छाया में सक्रिय आतंकी तंत्र को बेअसर करने की खुली छूट दे दी है। आतंकवाद का समर्थन और वित्तपोषण करने वालों को बहुत भारी कीमत चुकानी होगी।

उपराज्यपाल ने दुष्प्रचार और प्रचार की चुनौतियों पर भी चर्चा की और अधिकारियों को इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा, अपनी विघटनकारी गतिविधियों और दुष्प्रचार अभियान को अंजाम देने के लिए साइबर स्पेस का शोषण करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमें कट्टरपंथी और चरमपंथी विचारों का आक्रामक तरीके से मुकाबला करना चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कोर पुलिसिंग और जनता के बीच विश्वास निर्माण, सार्वजनिक शिकायतों के निवारण और स्थानीय समुदायों से जुड़ने से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहा। उपराज्यपाल ने पुलिस बल और आम नागरिक के बीच विश्वास पर आधारित मजबूत संबंध बनाने पर भी जोर दिया।

मुख्य सचिव ने 7वीं राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक की अध्यक्षता की

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के कार्यान्वयन में संतुष्टि को तेज करने पर जोर दिया गया
उपायुक्त को टावर स्थापित करने के लिए साइट आवंटन के जिला स्तर के मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया

श्रीनगर



जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के कार्यान्वयन को गति देने के लिए, मुख्य सचिव अटल डल्लू ने नागरिक सचिवालय श्रीनगर में 7वीं राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में आयुक्त सचिव वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण सहित समिति के सदस्य जिनमें आयुक्त सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आयुक्त सचिव आवास एवं

शहरी विकास विभाग, सचिव लोक निर्माण विभाग, सदस्य संयोजक, अतिरिक्त डीजीटी जम्मू-कश्मीर एलएसए दूरसंचार विभाग जम्मू, सीजीएम भारत संचार निगम लिमिटेड जम्मू-कश्मीर, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में प्रमुख सचिव विद्युत विकास विभाग, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज, जम्मू, सांबा,

उधमपुर, श्रीनगर, शोपियां और बारामूला के डीसी भी शामिल हुए।

बैठक में छठी एसबीसी बैठक के निर्णयों के विस्तृत कार्य बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें बीएसएनएल द्वारा क्रियान्वित की जा रही 4जी सेचुरेशन परियोजना, पंक्ति, 5जी कार्यान्वयन योजना, खोदने से पहले कॉल करें, भारतनेट/संशोधित भारतनेट परियोजना और अन्य मुद्दे शामिल थे।

बैठक को संबोधित करते हुए अटल डल्लू ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के कार्यान्वयन की संतुष्टि को तेज करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि मौलिक प्रगति हासिल की गई है और लक्ष्य हासिल करने के लिए बाधाओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया है।

मुख्य सचिव ने डीसी को सीबीयूडी के लिए डीएलटीसी बैठक आयोजित करने और जिला स्तर पर टावरों के निर्माण के लिए साइट आवंटन मुद्दों के समाधान का निर्देश दिया।

मोबाइल टावरों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने संबंधितों को जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति दर्शाने और संपूर्ण डेटा अपडेट करने का निर्देश दिया।

इस दौरान मुख्य सचिव ने प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत, अस्वीकृत, वापस लिये गये, प्रक्रियाधीन और लंबित मामलों के संबंध में आरओडब्ल्यू आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की।

भविष्य में, उन्होंने समग्र प्रगति और फास्ट-ट्रैकिंग अनुप्रयोगों के प्रबंधन के लिए गतिशील पोर्टल के साथ सीबीयूडी के एकीकरण का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने श्रीनगर, बांदीपोरा और गांदरबल के जन प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया

विधायकों ने प्राथमिकता वाले विकास कार्यों, सार्वजनिक उन्मुख परियोजनाओं के लिए उदार वित्त पोषण मांगा

श्रीनगर

व्यापक बजट-पूर्व विचार-विमर्श जारी रखते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के नागरिक सचिवालय में कश्मीर के विभिन्न जिलों के जन प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कीं।

मुख्यमंत्री ने श्रीनगर, गांदरबल और बांदीपोरा जिलों के जिला विकास परिषदों के अध्यक्षों और विधान सभा के सदस्यों के साथ बजट-पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की।

बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, प्रमुख सचिव वित्त संतोष डी. वैद्य, महानिदेशक बजट एम.एस. मलिक भी उपस्थित थे। महानिदेशक व्यय सज्जाद हुसैन और श्रीनगर, गांदरबल और बांदीपोरा के उपायुक्त प्रतिभागियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

चर्चा के दौरान, श्रीनगर के विधायकों ने राजधानी शहर के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्राथमिकता वाली विकासात्मक परियोजनाओं और प्रमुख जन कल्याण पहलों के लिए उदार वित्त पोषण की मांग की। बैठक में विधायक अली मुहम्मद सागर, मुबारक गुल, शमीम फिरदौस, तनवीर सादिक, अहसान परदेसी, सलमान अली सागर ने अपनी योजनाओं पर चर्चा की।



परामर्श में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें वैकल्पिक मार्गों की खोज करके यातायात भीड़ कम करना, श्रीनगर शहर में पार्किंग स्थल, सड़कों पर वाहनों के दबाव को कम करना, फ्लाईओवर, सामुदायिक हॉल का निर्माण शामिल है। जल निकासी की बहाली, खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार, ऊर्ध्वाधर आवास परियोजनाएं, डल के अंदरूनी हिस्सों की ड्रेजिंग और एक कुशल जल निकासी प्रणाली के विकास पर भी चर्चा की गई।

विधायकों ने बेहतर पेयजल गुणवत्ता, उन्नत सीवेज उपचार संयंत्रों, बेहतर बिजली आपूर्ति और एक प्रभावी ठोस अपशिष्ट

प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने अच्चन लैंडफिल साइट पर कचरे के वैज्ञानिक निपटान, नई डंपिंग साइटों की पहचान करने, डल झील में जल एम्बुलेंस शुरू करने, इसकी नहरों को खोदने, अग्नि पीड़ितों के लिए राहत बढ़ाने, आंतरिक सड़कों और बुलेवार्ड रोड को चौड़ा करने और मौजूदा बाधाओं को दूर करने के महत्व पर जोर दिया। श्रीनगर के युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते बनाने और वार्षिक बजट में कुछ प्रावधान करने की मांग पर भी जोर दिया गया।

बांदीपोरा और गांदरबल जिलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ आयोजित

बैठक में डीडीसी बांदीपोरा के अध्यक्ष, गुरेज, सुबल और बांदीपोरा निर्वाचन क्षेत्रों के विधायक और गांदरबल जिले के कंगन निर्वाचन क्षेत्र के विधायक शामिल हुए।

विशेष रूप से, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गांदरबल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और उन्हें गांदरबल जिले के लिए बजट प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक के दौरान, विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विभिन्न विकासात्मक प्रस्ताव और बुनियादी ढांचा योजनाएं प्रस्तुत कीं, जिनमें अग्निशमन केंद्र, बांदीपोरा-गुरेज

सड़क के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा, दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवारत अधिकारियों के लिए भत्ते, एचईपी परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार, बांदीपोरा स्वास्थ्य संस्थानों में महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण प्रदान करना, जनजातीय क्षेत्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं, लघु सिंचाई खूलों को पुनर्जीवित करना, मछली पालन और पर्यटन केंद्रित स्थानों में आय सृजन के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के साथ-साथ सड़क, जल आपूर्ति, बिजली वितरण और सिंचाई के संबंध में बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

चर्चा पर्यटन को बढ़ावा देने और युवा सेवाओं और खेल सुविधाओं को बढ़ाने पर भी केंद्रित रही। विधायकों ने विभिन्न परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया और अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख सार्वजनिक मांगों को हल किया।

प्रत्येक जिले के उपायुक्तों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जल निकासी, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, और बिजली क्षेत्र सहित प्रमुख क्षेत्रों में जिला परिदृश्य, जनसांख्यिकी और मौजूदा बुनियादी ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

प्रस्तुतियों में जिला कैपेक्स, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और वर्तमान योजना के तहत चल रही परियोजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई।

सभी विधायकों ने बजट पूर्व विचार-विमर्श में उन्हें शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और सरकार के समावेशी दृष्टिकोण को स्वीकार किया।

उपायुक्त ने किश्तवाड़ में एचएडीपी के कार्यान्वयन की समीक्षा की

किश्तवाड़

किश्तवाड़ के उपायुक्त राजेश कुमार शवन ने जिले में समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्राप्त उपलब्धियों का आकलन करने के लिए एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में बोलते हुए, डीसी ने निर्धारित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए समयबद्ध दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। डीसी ने किसान उत्पादक संगठनों के विस्तार पर जोर दिया और अधिकारियों को अगले सप्ताह में सभी लंबित आवेदनों को संसाधित करने और अनुमोदन के लिए जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। विविध कृषि पद्धतियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने पदाधिकारियों से टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए जिले भर में बाजरा, लैवेंडर, गेंदा और तेल बीज की खेती को बढ़ावा देने का आग्रह किया।

बैठक में सीपीओ शाहनवाज बाली, एसीआर इदरीस लोन, एसीडी फुलैल सिंह, सीएओ अमजद हुसैन मलिक, सीएओ साजिद मुस्तफा,



डीएसएचओ डॉ. जमील नासिर, एलडीएम, डीएओ और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उपायुक्त ने पुंछ में जल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया

पुंछ

जिले में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक सक्रिय कदम में, उपायुक्त पुंछ विकास कुंडल ने जल योजनाओं का व्यापक निरीक्षण किया। अधीक्षक अभियंता मोहम्मद ताज चौधरी, कार्यकारी अभियंता राजीव घई के अलावा एईई, जेई और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ, उपायुक्त ने डिंगला और चकतरू सहित प्रमुख जल योजनाओं का दौरा किया।

निरीक्षण के दौरान, उपायुक्त ने स्थानीय निवासियों से उनकी जल

संबंधी चिंताओं को समझने के लिए बातचीत की। उन्होंने कमी को रोकने के लिए स्थापना के कुशल कामकाज और उचित रखरखाव के महत्व पर जोर दिया।

समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश में उपायुक्त ने एसई को कनिष्ठ अभियंताओं के साथ योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा, उन्होंने एक्सईएन को डिंगला और चकतरू जल योजनाओं को 10 दिनों के भीतर चालू करने का आदेश दिया।

आज का राशिफल



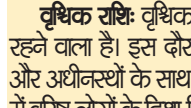
मेष

मेष राशि: मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह परिश्रम और प्रयास करने पर पूरा फल प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके कार्य में आ रही अड़चनें स्वतः दूर होती हुई नजर आएंगी। स्वजनों एवं शुभचिंतकों का पूरा सहयोग और समर्थन पूरे सप्ताह मिलता रहेगा। करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए गुडलक लिए हुए है। बेरोजगार लोगों को रोजगार की और पहले से कार्यरत नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कद एवं पद में वृद्धि का सुख-सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा उम्मीद से कहीं ज्यादा फलदायी और लाभप्रद साबित होगी। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रह सकता है। इस सप्ताह आपको लोगों के साथ बात-व्यवहार करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसी बात न कहें, जिसका लोग आपकी बात अथवा व्यवहार को लेकर गलत मतलब निकाल लें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग्स की कद्र करें और उनका दिल दुखाने से बचें। मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने की आशंका बनी रहेगी।



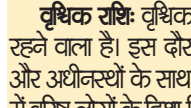
तुला

तुला राशि: तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य में शार्टकट लेने अथवा नियमों का उल्लंघन करने से बचना चाहिए अन्यथा लाभ की जगह नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में किसी कार्य विशेष को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को लेकर मन परेशान रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अपने उच्च अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग और समर्थन कम मिल पाएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र में परिश्रम के अनुसार प्रोत्साहन अथवा प्रशंसा न मिलने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। भूमि-भवन अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपकी चिंता के कारण बन सकते हैं। इस दौरान किसी भी मामले को लेकर कोर्ट-कचहरी जाने की बजाय बातचीत के जरिए सुलझाना बेहतर रहेगा। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए सामान्य से कहीं ज्यादा परिश्रम करना होगा। तुला राशि के जातक इस सप्ताह वाहन सावधानी से चलाएं। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान को लेकर विशेष सावधानी बरतें। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह ग्रहों की चाल आपके लिए शुभ नहीं कही जा सकती है। इस सप्ताह किसी विषय को लेकर परम प्रिय व्यक्ति के साथ अनबन हो सकती है।



वृषभ

वृष राशि: वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा-उतार चढ़ाव लिए रह सकता है। करियर हो या कारोबार इस सप्ताह आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर ही मनचाही सफलता मिल पाएगी। नौकरीपेशा लोगों को अपना कार्य किसी दूसरे पर छोड़ने की भूल करने से बचना होगा, अन्यथा उसके बिगड़ने पर मान-सम्मान को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इस सप्ताह आपको अपनी उर्जा एवं धन आदि का भी प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। जिसके कारण आपका बना-बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। इस सप्ताह घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। कारोबार में मंदी बनी रह सकती है। इस सप्ताह किसी भी जोखिम भरे निवेश से बचें। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के संवाद बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर स्वजनों के साथ मतभेद हो सकता है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और उसका बेवजह प्रदर्शन न करें। वैवाहिक सुख के लिए अपने जीवनसाथी के प्रति ईमानदार रहें।



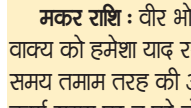
वृश्चिक

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध सामान्य फलदायी रहने वाला है। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों और अधीनस्थों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ लोगों के दिशा-निर्देश का पालन करते हुए अपने कार्य को समय पर पूरा करने का प्रयास करें अन्यथा आपको परेशानियां डेलनी पड़ सकती हैं। यदि आप विदेश में करियर अथवा कारोबार आदि के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इससे जुड़ी सफलता के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। इस सप्ताह कठिन परिश्रम और प्रयास के बावजूद कारोबार में मनचाही उन्नति और लाभ की प्राप्ति न होने पर मन में निराशा के भाव जग सकते हैं। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध चुनौती भरा रह सकता है। इस दौरान आपको अपने कंप्यूटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह किसी से ऐसा वादा न करें, जिसे पूरा करना आपके लिए कठिनाई का सबब बन जाए। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास को बनाए रखना चुनौती भरा रह सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति की दरखलवाजी से रिश्तों में खटास आ सकती है। जीवनसाथी की खराब सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा।



धनु

धनु राशि: धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह सोचे हुए अधिकांश समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। घर और बाहर दोनों जगह लोगों का समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। जिसके कारण आपके भीतर उत्साह और सकारात्मकता बनी रहेगी। इस सप्ताह सौभाग्य का साथ मिलने के कारण न सिर्फ आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी बल्कि अटके हुए कार्य भी तेजी से पूरे होते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के मध्य में सत्ता-सरकार से जुड़े प्रभावी लोगों के साथ संपर्क होगा। राजनीति एवं समाज से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। वित्तीय दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए उत्तम साबित रहने वाला है। नौकरीपेशा लोगों की आय के नये स्रोत बनेंगे। पूर्व में किसी योजना में किए गये निवेश से लाभ होगा। स्थायी संपत्ति और वाहन सुख की प्राप्ति संभव है। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।



मकर राशि: वीर भोग्य वसुंधरा। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह इस प्रेरक वाक्य को हमेशा याद रखना होगा क्योंकि उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते समय तमाम तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह सोचे हुए कार्य समय पर न पूरे होने अथवा उसमें अड़चन आने से आपके भीतर झुंझलाहट और रोध की अधिकता देखने को मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों की जिम्मेदारियों में बदलाव होने की आशंका है। इस सप्ताह लोगों के साथ वाद-विवाद करने से बचें और यदि एक कदम पीछे करने पर दो कदम आगे जाने की संभावना बने तो ऐसा करने में बिल्कुल संकोच न करें। इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण उनका बना-बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो जोखिम भरे धन निवेश से बचें। यात्रा के दौरान अपने सामान का विशेष खयाल रखें और किसी को सोच-समझकर ही धन उधार दें। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए मकर राशि के जातकों को अनावश्यक विवाद से बचते हुए लोगों के साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं अन्यथा अपयश मिलने की आशंका है।

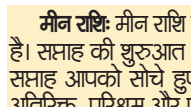


मकर



कुंभ

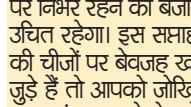
कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत भले ही कुछेक दिक्कतों के साथ हो लेकिन उत्तरार्ध तक सब कुछ आपके अनुकूल होता नजर आएगा। ऐसे में किसी भी कार्य में यदि कोई समस्या आती है तो अपना आपा न खोएं और शांत मन से उसका समाधान खोजने का प्रयास करें। नौकरीपेशा लोगों पर इस सप्ताह के प्रारंभ में कामकाज का अतिरिक्त दबाव बना रह सकता है, लेकिन सुखद पहलू यह है कि उसे निबटाने में आपके अधीनस्थ और शुभचिंतक काफी मददगार साबित होंगे। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह धन लाभ होने के साथ खर्च भी खूब होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान अचानक से लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद एवं नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने कारोबारी रणनीति में कुछेक बदलाव ला सकते हैं। हालांकि ऐसा करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है।



मीन राशि: मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी आपाधापी भरा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही आप पर कामकाज का अतिरिक्त दबाव बना रहेगा। इस सप्ताह आपको सोचे हुए कार्यों को समय पर मनचाहे तरीके से पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने पड़ेंगे। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं अपने कार्यों को सही तरीके से करने का प्रयास करना उचित रहेगा। इस सप्ताह अपने समय और धन का प्रबंधन करके चलें और विलासिता की चीजों पर बेवजह खर्च करने से बचें, अन्यथा बाद में वित्तीय स्थिति डगमगा सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। इस सप्ताह किसी भी कार्य में शार्टकट लेने अथवा नियम का उल्लंघन करने से बचें, अन्यथा बेवजह की परेशानियां डेलनी पड़ सकती हैं। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको मनचाहे रोजगार प्राप्ति के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए मीन राशि के जातकों को दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हुए लोगों के साथ विनम्रता से पेश आने की आवश्यकता बनी रहेगी। प्रेम संबंध में दिखावा करने से बचें।



मीन



कन्या

कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको बीते कुछ समय से चले आ रही परेशानियों से उबरने का अवसर प्राप्त होगा लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध तक एक बार फिर परिस्थितियां आपके प्रतिकूल होती नजर आएंगी। इस सप्ताह आपको अपने किसी भी कार्य में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए अन्यथा हाथ आई सफलता भी फिसल कर निकल सकती है। आपको अपने समर्पित भाव से प्रयास करने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो पाएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध अचानक से आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको छोटे-छोटे कार्यों को करने के लिए अधिक परिश्रम और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। यदि आप भूमि-भवन के य-वि य की योजना बना रहे हैं तो कागज की अच्छी तरह से जांच कर लें और धन के लेनदेन में खूब सावधानी बरतें। व्यवसाय से जुड़े लोगों का मन कारोबारी की धीमी प्रगति के कारण थोड़ा निराश रहेगा। बाजार में अपनी साख को बनाए रखने की चिंता सताएगी।



कन्या

पृष्ठ 1 का शेष

उपराज्यपाल ने एसएमवीडीयू के स्वागत

क्षमताओं का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित करने और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए शैक्षणिक संस्थानों को सबसे शक्तिशाली साधन में बदलने के लिए कहा।

यह हमारे शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे नवीन शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करें और जिज्ञासा को बढ़ावा दें, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, नवाचार को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को छात्रों को आजीवन सीखने के कौशल के लिए प्रेरित करने के लिए अपने जीवन के अनुभव साझा करने चाहिए जो भविष्य को आकार देंगे।

उपराज्यपाल ने सभी स्वागत छात्रों को उत्पादक और उवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पदक तालिका में लड़कों से आगे निकलने और सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन और इंफोसिस फाउंडेशन प्राइज में भी आगे रहने के लिए छात्रों को बधाई दी।

श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय ने लेखक और इतिहासकार पद्मश्री पंडित शिव दत्त निर्मोही और पूर्व सीईओ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण डॉ. राम सेवक शर्मा को भी मानद उपाधि प्रदान की।

माननीय उपराज्यपाल की पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उच्च शिक्षा मंत्री सुश्री सकीना इतू, संसद सदस्य जुगल किशोर शर्मा, उपकुलपति एसएमवीडीयू प्रो. प्रगति कुमार, विभिन्न विषयविद्यालयों के उपकुलपति, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के एचओडी, नागरिक और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, संकाय सदस्य, छात्र और उनके माता-पिता भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्कॉस्ट-जम्मू में

स्तर पर शासन को मजबूत करने में पिछली सरकारों, विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के योगदान को स्वीकार किया।

उन्होंने कहा पंचायती राज प्रणाली पहली बार जम्मू और कश्मीर ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत शुरू की गई थी। समय के साथ, पंचायत प्रणाली विकसित हुई है, हर सरकार इसे मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रही है।

पंचायत चुनावों के महत्व के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने स्थानीय शासन में उच्च स्तर की सार्वजनिक भागीदारी की ओर इशारा किया। हमने देखा है कि जहां संसदीय चुनावों में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम होता है, वहीं विधानसभा चुनावों में यह बढ़ जाता है। हालांकि, पंचायत चुनावों में उच्चतम स्तर की भागीदारी देखी जाती है क्योंकि ये संस्थाएँ लोगों के सबसे करीब होती हैं।

उमर अब्दुल्ला ने नवनियुक्त पंचायत सचिवों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ग्रामीण विकास के लिए आवंटित सरकारी धन का उपयोग प्रभावी ढंग से और भ्रष्टाचार के बिना किया जाए।

उन्होंने जोर देकर कहा, योजनाएं चाहे केंद्र प्रायोजित हों या जम्मू-कश्मीर प्रायोजित अधिकतम सार्वजनिक लाभ सुनिश्चित करते हुए ईमानदारी से लागू की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, आपको दबावों और निर्णयों को प्रभावित करने के प्रयासों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपका कर्तव्य न्याय को बनाए रखना और गरीबों की सेवा करना है।

उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि सरकारें बदलती रहती हैं, लोक सेवकों की जिम्मेदारी स्थिर रहती है।

राजनीतिक बदलावों के बारे में चिंता मत करो, आपका ध्यान समर्पण के साथ लोगों की सेवा करने पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि वह आने वाले वर्षों में नियुक्त व्यक्तियों के साथ बातचीत करना जारी रखेंगे और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपनी सरकार के समर्थन का वादा करेंगे।

यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। आज, हम यहां हैं, लेकिन कल, हम क्षेत्र में मिलेंगे, शासन में सुधार के लिए मिलकर काम करेंगे। मैं आपके क्षेत्रों का दौरा करने और आपके काम के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए उत्सुक हूँ।

20 नवनियुक्त-कश्मीर और जम्मू संभागों से 10-10-को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से नियुक्ति आदेश प्राप्त हुए। समारोह में बोलते हुए, कृषि उत्पादन और आरडीडी मंत्री, जावेद अहमद डार ने नियुक्तियों को बधाई दी और उनसे

ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे ईमानदारी के साथ सेवा करने का आग्रह करते हुए चुनौतियों पर काबू पाने में सरकारी समर्थन का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम बानी, स्कॉस्ट-जम्मू के उपकुलपति बी.एन. त्रिपाठी, सचिव आरडीडी ऐजाज असद, आरडीडी कश्मीर और जम्मू के निदेशक, नव नियुक्त पंचायत सचिव, उनके माता-पिता और अन्य संबंधित लोग भी उपस्थित थे।

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर दिव्यांगजनों को

दिव्यांगजनों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के अपने संकल्प को दोहराते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा मैं हमेशा भगवान के उपहार और दूसरों के लिए अच्छा करने में विश्वास करता हूँ। मैंने ऐसे कदम उठाना प्रशासन का प्राथमिक लक्ष्य बनाया है जिससे दिव्यांगजनों को समाज में मुख्यधारा में लाया जा सके। 2020 में मैंने प्रशासन में एक बहुआयामी दृष्टिकोण पेश किया था ताकि दिव्यांगजन अपनी क्षमता का एहसास कर सकें और विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सकें।

उपराज्यपाल ने दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरणों को सुलभ बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों पर प्रकाश डाला और कहा मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि प्रत्येक दिव्यांगजन के पास सहायक उपकरणों तक पहुंच हो जो उन्हें सशक्त बनाए और विकलांगता के प्रभाव को कम करें।

उपराज्यपाल ने आगे कहा, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, अंग कृत्रिम अंग और मोटर चालित स्कूटी जैसे उपकरण, जो कार्यात्मक क्षमता में सुधार करते हैं और दिव्यांगों को स्वतंत्र रूप से जीने में मदद करते हैं, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में उपलब्ध कराया गया है।

उपराज्यपाल ने व्यक्तिगत और सामाजिक सेवा संगठनों से दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त उपकरण खरीदने में मदद करने का आग्रह किया।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नवप्रवर्तकों से आधुनिक तकनीक की मदद से दिव्यांगजनों के लिए अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल सहायता और उपकरणों का आविष्कार करने का भी आग्रह किया।

उपराज्यपाल ने समाज कल्याण विभाग को दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए मिशन मोड पर काम करने का निर्देश दिया।

उन्होंने दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए समर्पित उपायों और विभिन्न मानकों के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति में किए गए आवश्यक बदलावों को साझा किया।

उपराज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री से जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में दिव्यांगजनों के लिए भव्य मेला आयोजित करने का आग्रह किया।

उन्होंने देश के अन्य हिस्सों में मेलों में जम्मू-कश्मीर के दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के लिए एक मंच प्रदान करने के आश्वासन के लिए केंद्रीय मंत्री को भी धन्यवाद दिया।

उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों, विभिन्न सरकारी संस्थानों और नागरिक समाज समूहों द्वारा लगाए गए स्टालों का दौरा किया। उन्होंने लाभार्थियों को गतिशीलता उपकरण और स्वीकृति पत्र भी सौंपे।

उपराज्यपाल ने भाग लेने वाले कारीगरों और उद्यमियों को उनके व्यवसाय को बढ़ाने और उनके उत्पादों के विपणन में प्रशासन द्वारा सभी समर्थन और आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री सकीना इतू, संसद सदस्य जुगल किशोर शर्मा, आयुक्त सचिव समाज कल्याण विभाग संजीव वर्मा, संयुक्त सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग राजीव शर्मा, संभागीय आयुक्त जम्मू रमेश कुमार, वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, कलाकार, कारीगर और उद्यमी तथा समाज के सभी क्षेत्रों से सम्बंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

मंदीप कौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियों की समीक्षा की

जम्मू

आवास एवं शहरी विकास विभाग की आयुक्त सचिव मंदीप कौर ने जम्मू नगर निगम के कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियों की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

देश भर में शहरी स्थानीय निकायों के बीच एक स्वच्छता सर्वेक्षण 'स्वच्छ सर्वेक्षण' के बारे में बोलते हुए, मंदीप कौर ने आगामी सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग हासिल करने के लिए स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिक भागीदारी में सुधार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने संबंधितों को स्वच्छता बनाए रखने और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नवीन समाधान लागू करने का निर्देश दिया।

डॉ. देवांश यादव ने स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए जेएमसी और अन्य शहरी निकायों द्वारा पहले ही उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने पूरे जम्मू-कश्मीर में स्वच्छ और



अधिक टिकाऊ शहरी वातावरण प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

मंदीप कौर ने आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा शुरू किए गए गणतंत्र दिवस से पहले स्वच्छता अभियान 'स्वच्छतंत्र' के दौरान यूएलबी द्वारा की गई गतिविधियों की भी समीक्षा की। इस अभियान ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ शहरी वातावरण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया।

अभियान के दौरान, 1032 से अधिक

विभिन्न स्वच्छता और सफाई गतिविधियों की गईं, जिनमें नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और 3,50,00 से अधिक लोगों ने यूएलबी द्वारा की गई विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों में भी भाग लिया। इसके अलावा, 2,21,000 से अधिक नागरिकों ने निरंतर स्वच्छता और साफ-सफाई की शपथ ली। 188 कचरा बिंदुओं और 52 जल निकायों को साफ किया गया।

'स्वच्छतंत्र' के दौरान, जम्मू-कश्मीर के सभी 80 यूएलबी के लिए अपशिष्ट पृथक्करण का महत्व विषय पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता

आयोजित की गई थी। चित्रकला प्रतियोगिता में 1040 लोगों ने भाग लिया था, जो स्वच्छता पहल के प्रति लोगों विशेषकर युवाओं के उत्साह को दर्शाता है। मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, 2.0 को शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, जम्मू/कश्मीर और जेएमसी/एसएमसी से 26 सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग प्राप्त हुई। मिशन निदेशक ने न्यायाधीशों का एक पैनेल तैयार किया जिसने प्राप्त 26 सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग का मूल्यांकन किया। डोडा की अक्सा, शोपियां की सना फिरदौस और जम्मू की रक्षा गुरुंग ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 50,000 रुपये, 25,000 रुपये तथा 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। तीन सांत्वना पुरस्कार भी क्रमशः शोपियां से अर्जुमन जमीन, जम्मू से सुनैना कपूर और उधमपुर से माही मन्हास को दिए गए।

आयुक्त सचिव ने मापने योग्य प्रभाव लाने, समुदाय के भीतर अधिक जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देने और स्वच्छ और

स्वस्थ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ऐसी सभी स्वच्छता पहलों में अधिक नागरिकों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में जम्मू-कश्मीर के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र, सार्वजनिक भागीदारी में वृद्धि और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को बढ़ाने के आह्वान के साथ बैठक संपन्न हुई।

बैठक में आयुक्त जेएमसी डॉ. देवांश यादव, निदेशक शहरी स्थानीय निकाय जम्मू मनीषा सरिन, संयुक्त आयुक्त अब्दुल स्तार, स्वास्थ्य अधिकारी जेएमसी डॉ. विनोद कुमार शर्मा और जेएमसी के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारी और कर्मचारी और जम्मू-कश्मीर की अन्य नगर परिषदों और नगर समितियों के कार्यकारी अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कश्मीर में बजट पूर्व परामर्श का समापन किया, शोपियां, कुपवाड़ा के जनप्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया

निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रस्ताव कैपेक्स बजट में शामिल किए जाएंगे-मुख्यमंत्री

श्रीनगर

आगामी बजट 2025-26 के लिए कश्मीर में बजट पूर्व परामर्श का समापन करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के नागरिक सचिवालय में शोपियां और कुपवाड़ा जिलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने जिला विकास परिषदों के अध्यक्षों और शोपियां और कुपवाड़ा जिलों के विधानसभा सदस्यों के साथ बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की।

बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता और प्रमुख सचिव वित्त संतोष डी. वैद्य भी शामिल हुए। जबकि शोपियां और कुपवाड़ा जिलों के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

बैठकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला पूंजीगत व्यय बजट में कार्यों का प्रस्ताव करते समय उन परियोजनाओं पर



ध्यान दिया जाना चाहिए, जिन्हें दो से तीन साल की उचित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सकता है और जो आवंटित धन के भीतर स्पष्ट वितरणों के साथ हों। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया, जो बजट चक्र के साथ संरेखित हों और जनता की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करें।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बजट पूर्व परामर्श आयोजित करने का उद्देश्य हितधारकों और जनप्रतिनिधियों से उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त करना है, जो जमीनी हकीकत से अवगत हैं और ऐसे कार्यों का प्रस्ताव करते हैं जो महत्वपूर्ण हैं और समग्र जन कल्याण के लिए हैं। इससे पहले, चर्चा के दौरान, शोपियां के विधायकों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के

लिए विभिन्न विकास प्रस्ताव और बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं प्रस्तुत कीं, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, आरएडबी, पीडीडी, पीएचई के तहत बुनियादी ढांचे के संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बजट 2025-26 में सिंचाई उद्देश्यों के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने पर जोर दिया। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उन्होंने जिलों में पर्यटन की संभावनाओं को तलाशने की भी मांग की।

इसी तरह, एक अन्य बजट पूर्व परामर्श बैठक में मुख्यमंत्री ने जिला विकास परिषद के अध्यक्ष और कुपवाड़ा जिले के विधायकों के साथ विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की। परामर्श के दौरान, डीडोसी अध्यक्ष और करनाह, त्रेहगाम, कुपवाड़ा, लोलाब और लंगेट निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों ने स्थानीय आबादी की मांगों को शामिल करते हुए विकास

प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, जिनमें सड़कों का उन्नयन और चौड़ीकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे का उन्नयन, पीएचई क्षेत्र का विस्तार आदि शामिल हैं।

चर्चा के दौरान, जनप्रतिनिधियों ने जिले में विशेष रूप से बंगस, लोलाब और कुपवाड़ा के अन्य क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री के सलाहकार, नासिर असलम वानी ने कुपवाड़ा जिले के विधायकों की मांगों का समर्थन किया और कहा कि विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर को और अधिक पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ पूरी तरह कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने कुपवाड़ा शहर से उचित कचरा निपटान तंत्र, जल की कमी को दूर करने के लिए वर्षा जल संचयन, सिंचाई के लिए बने कुपवाड़ा जल निकाय से गाद निकालने, कुपवाड़ा को मादक पदार्थों की तस्करी के मार्ग के रूप में विकसित होने से रोकने के लिए कहा, जिस पर विधायक करनाह ने भी ध्यान दिलाया और कहा कि इस क्षेत्र से मादक पदार्थों की समस्या को समाप्त किया जाना चाहिए।

मेडिकल कॉलेज के लिए स्थल को अंतिम रूप देने पर भी जोर दिया गया, ताकि इसे बिना किसी देरी के स्थापित किया जा सके और एसडीएच को जिला अस्पताल का दर्जा दिया जा सके।

विधायकों ने कुपवाड़ा से बांदीपोरा रोड, कुपवाड़ा बाईपास रोड और कुपवाड़ा में मिनी सचिवालय के निर्माण पर भी जोर दिया।

इससे पहले, शोपियां और कुपवाड़ा जिलों के उपायुक्तों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जल निकासी, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और बिजली क्षेत्र सहित प्रमुख क्षेत्रों में जिले की रूपरेखा, जनसांख्यिकी और मौजूदा बुनियादी ढांचे को रेखांकित करते हुए विस्तृत प्रस्तुतियां दीं।

प्रस्तुतियों में जिला पूंजीगत व्यय, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और वर्तमान योजना के तहत चल रही परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।

सभी विधायकों ने बजट पूर्व परामर्श में उन्हें शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और बजट 2025-26 की चल रही तैयारियों के संबंध में सरकार के समावेशी दृष्टिकोण की सराहना की।

व्यक्तिगत बैठकों के दौरान, मुख्यमंत्री ने जिला विकास परिषदों के अध्यक्षों, विधान सभा सदस्यों और ट्रेड यूनियनों, उद्योगपतियों, उद्यमियों, शिक्षा, कृषि, बागवानी, अर्थशास्त्र और अन्य क्षेत्रों और सेवाओं के विशेषज्ञों सहित हितधारक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बजट सार्वजनिक हित को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया हो।

उपराज्यपाल ने नए जम्मू-कश्मीर में नई उम्मीद के समारोह जश्न-ए-जम्मू कश्मीर का उद्घाटन किया

‘जश्न-ए-जम्मू कश्मीर’ हमारी समृद्ध लोक संस्कृति को याद करने का अवसर है, जो राष्ट्र के लिए गौरव का स्रोत है और विविधता में एकता के आदर्शों को मजबूत करता है-एलजी

में चाहता हूं कि हमारे प्रतिभाशाली कलाकार समाज के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएं-एलजी सिन्हा

इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले लगभग 350 कलाकार विभिन्न कलाओं, लोक नृत्यों और अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत की प्राचीन सभ्यता को दर्शाते हैं-एलजी

एलजी ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए कलाकारों को सम्मानित किया

जम्मू

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभिनव थिएटर में नया जम्मू-कश्मीर में नई आशा



का उत्सव जश्न-ए-जम्मू कश्मीर का उद्घाटन किया।

अपने संबोधन में, उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी और जम्मू कश्मीर आर्टिस्ट एसोसिएशन के सहयोगात्मक प्रयास की सराहना की।

उपराज्यपाल ने कहा जश्न-ए-जम्मू

कश्मीर हमारी समृद्ध लोक संस्कृति को याद करने का एक अवसर है, जो राष्ट्र के लिए गर्व का स्रोत है और विविधता में एकता के आदर्शों को मजबूत करता है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले लगभग 350 कलाकार विभिन्न कलाओं, विभिन्न प्रकार के लोक नृत्यों और अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं

जो भारत की नरम शक्ति और इसकी प्राचीन सभ्यता को दर्शाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर की असाधारण यात्रा पर बोलते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि माननीय प्रधान मंत्री के मार्गदर्शन में यूटी सरकार 'विकास भी विरासत भी' के संकल्प के साथ काम कर रही है।

उन्होंने कहा, यह गर्व की बात है कि एक तरफ उद्योग और ढांचागत विकास नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर में कला और संस्कृति का पुनरुद्धार हुआ है। जम्मू कश्मीर के कलाकारों ने कला, लोक संगीत, रंगमंच, सिनेमा, साहित्य के विभिन्न रूपों के माध्यम से 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत किया है। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रतिभाशाली कलाकार समाज के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएं। कलाकार नागरिकों को नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और सामाजिक प्रगति को ऊर्जा प्रदान करते हैं। विकास की गति को बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक है कि शिक्षक, वैज्ञानिक और कलाकार मिलकर काम करें और देश की सेवा करें।

उपराज्यपाल ने कलाकारों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति प्रशासन की

प्रतिबद्धता भी दोहराई।

उन्होंने अभिनव थिएटर को सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियों के केंद्र में बदलने में जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के योगदान की सराहना की।

जम्मू-कश्मीर में संसदीय और विधान सभा चुनावों के शांतिपूर्ण संचालन पर बोलते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि हाल के चुनावों के दौरान कोई हेराफेरी या पुनर्मतदान नहीं हुआ था।

उन्होंने कहा, कई लोगों को हिंसा, जानमाल के नुकसान की आशंका थी लेकिन पथराव की एक भी घटना की सूचना नहीं मिली।

इसके उपरान्त, उपराज्यपाल ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए विभिन्न कलाकारों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर आयुक्त सचिव संस्कृति विभाग के. रमेश कुमार, उपायुक्त जम्मू सचिन कुमार वैश्य, सचिव जेकेएसएल हरविंदर कौर, जम्मू-कश्मीर आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलजार अहमद भट्ट, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार, युवा और प्रमुख नागरिक उपस्थित थे।